राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार , 28 नवंबर 2025

वर्ष 14,अंक 225, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

15 साल के अंश की कोचिंग जाने की राह पर मौत..03

वोट चोर का झूठा नारा देने वाली कांग्रेस खुद है रिजर्वेशन चोरः पेरिका सुरेश..04

कौन है सुनाली खातून और उसका परिवार, जिसे भेज दिया गया बांग्लादेश, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वापस लेकर आओ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक गर्भवती महिला सुनाली खातून समेत 6 लोगों को उनकी नागरिकता के वेरिफिकेशन के बिना ही बांग्लादेश भेज दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराजगी दिखाई. देश की सबसे बड़ी अदालत ने मंगलवार (24 नवंबर) को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल किए. साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि इन सभी लोगों को वापस भारत लाया जाए 25 साल की सुनाली खातून और 5 अन्य लोगों को, जिन्हें इस साल जून में दिल्ली से हिरासत में लिया गया था. हिरासत में लिए जाने के 3 दिन के अंदर ही उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया. सुनाली के साथ-साथ उनके पति दानिश और उनके 8 साल के बेटे के अलावा एक और परिवार के 3 सदस्यों को बांग्लादेश भेज दिया गया था।

पहले लाओ, फिर नागरिकता पर फैसला करो

सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार ने एक और दिन की मोहलत मांगी, तो कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अंतरिम व्यवस्था के तहत, केंद्र सरकार को पहले सभी 6 लोगों को भारत वापस लाना होगा. उनके लौटने के बाद ही अधिकारी उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं और उनकी नागरिकता की स्थिति पर फैसला कर सकते हैं. मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते सोमवार (1 दिसंबर) को होनी है. मामला सुप्रीम कोर्ट तब पहुंचा जब केंद्र सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले के निर्देश पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही. 24 सितंबर को ही हाई कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों के अंदर सभी 6 लोगों को वापस लाने का आदेश दिया था. हालांकि इस आदेश पर अमल करने की जगह केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जो अब इस मामले की जांच कर रहा है।

26 जून को हिरासत में लिया गया परिवार

कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से वापस लाए जाने की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी उनकी वापसी पक्की करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, और इस वजह से नई ज्यूडिशियल जांच शुरू हो गई.

26 जून को, सुनाली और स्वीटी बीबी के परिवारों को, जिसमें उसके 6 और 16 साल के बेटे भी शामिल थे, दिल्ली पुलिस ने गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठिए होने के शक में उठाया था. जबकि इनका कहना था कि ये बंगाल से आए हुए हैं।

दस्तावेज में पश्चिम बंगाल के निवासी

कोर्ट में जमा किए गए डिटेल से पता चला है कि खातून और उनके साथ बांग्लादेश भेजी गई कम से कम एक और महिला के भारत से पुराने और पक्के सबूत वाले दस्तावेज हैं. उनके माता-पिता के नाम 2002 के इलेक्टोरल रोल में भी दर्ज हैं, जिससे पता चलता है कि वे 2 दशक से भी पहले वोटर के तौर पर देश में रजिस्टर्ड हो चुके थे. मिली जानकारी में खातून के पिता भोदू शेख और उनके पिता हातिम ताई शेख का भी जिक्र है. उनके परिवार ने 1952 से अब तक के जमीन के रिकॉर्ड भी दिखाए हैं, जिसमें देश में लगातार रहने और प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को दिखाया गया है।

बच्चों के लौटने का इंतजार: पिता शेख

अंग्रेजी वेबसाइट द वायर से बात करते हुए, भोदू शेख ने बताया कि आर्थिक की तंगी की वजह से उनके परिवार को दिल्ली आने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी, दामाद और पोते-पोतियां राजधानी में रद्दी कागज एकत्र करके और कबाड़ बेचकर गुजारा करने की उम्मीद में राजधानी आए थे. भोदू शेख बताते हैं, हम गरीब लोग हैं. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सरकार वहां पर हम पर इतनी कड़ी नजर रखेगी. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा, मैं अब इंतजार कर रहा हूं कि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मेरे बच्चे कब वापस आएंगे. इसी तरह स्वीटी बीबी के साथ भी ऐसा ही किया गया, और उन्हें भी खातून के साथ बांग्लादेश भेजा गया था. याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि डिपोर्टेशन का कोई भी फैसला लेने से पहले ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी चाहिए थी. लेकिन बिना वेरिफिकेशन के ही उन्हें देश से बाहर भेजना ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन है. सुनाली का परिवार से कोई संपर्क नहीं।

वहीं, सुनाली के परिवार का सुनाली के साथ कोई संपर्क नहीं हो सका है, हालांकि शुरुआत में वह किसी के फोन से उनसे बात करने में कामयाब रही थी. सुनाली की बहन करिश्मा, जो दिल्ली के रोहिणी में अपनी मां ज्योत्सनारा बीबी और सुनाली की 5 साल की बेटी के साथ रहती है, बताती हैं, उसके पकड़े जाने के बाद, हमारा संपर्क टूट गया है. लेकिन हमने सुना है कि उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था. हमें नहीं पता कि उसे किस तरह का इलाज मिल रहा है. हमारे पास बस कोर्ट की तारीखें हैं, कोर्ट की तारीखें. करिश्मा घरों में सहायिका का काम करती है, जबकि ज्योत्सनारा बर्तन बेचती हैं. दूसरी ओर, बांग्लादेश की एक कोर्ट ने भी ढाका में भारतीय दूतावास से भी इन लोगों को भारत वापस लाने में मदद करने को कहा है. याचिकाकर्ता के मुताबिक, इस आदेश के बाद भी भारत की ओर से बांग्लादेशी कोर्ट की रिक्वेस्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के यह साफ करने के बाद कि नागरिकता से जुड़े मामला तभी सुलझाया जा सकता है जब इन 6 लोगों को भारत वापस लाया जाएगा।

SIR को लेकर विपक्ष को तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी चुनाव आयोग के अधिकार पर मुहर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

देश के 12 राज्यों में चल रहे गहन वोटर पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है. आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर कराने के लेकर चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास ऐसा करने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है. शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया को रोकने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर इसमें कोई अनियमितता सामने आई तो वह तुरंत सुधार के आदेश देगा. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने राजद सांसद मनोज झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एसआईआर की जरूरत पर सवाल उठाने वाले तर्कों में दम नहीं है. सीजेआई ने याद दिलाया कि पिछले निर्देश पर चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में सुधार किया था और उसके बाद एक भी औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं हुई है।

कपिल सिब्बल ने क्या दी दलील?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया. उन्होंने दलील दी कि देश में लाखों-करोड़ों लोग निरक्षर हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते. उनका कहना था कि मतदाता गणना फॉर्म भरवाना ही अपने आप में लोगों को सूची से बाहर करने का हथियार बन गया है. सिब्बल ने कोर्ट से सवाल किया कि मतदाता को गणना फॉर्म भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है? चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं? आधार कार्ड में जन्म तिथि और निवास स्थान दर्ज है. 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति अगर स्व-घोषणा कर दे कि वह भारतीय नागरिक है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने के लिए यही काफी होना चाहिए।

क्या बोले सीजेआई सूर्यकांत?

इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने सिब्बल से कहा कि सिब्बल साहब, आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा है, वहां बहुत लोग वोट डालने नहीं आते. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव त्योहार की तरह मनाया जाता है. वहां हर व्यक्ति को पता होता है कि गांव का निवासी कौन है और कौन नहीं. वहां अधिकतम मतदान होता है और लोग अपने वोट को लेकर बहुत सजग रहते हैं. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट रखना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है और इसके लिए वह जरूरी कदम उठा सकता है. बेंच ने स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस शिकायत अभी तक सामने नहीं आई है, इसलिए इसे रोकने का कोई आधार नहीं बनता. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर कोई वास्तविक शिकायत या अनियमितता सामने आती है तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा और सुधार के आदेश देगा. कोर्ट ने यह भी भरोसा दिलाया कि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया की वजह से अपने अधिकार से वंचित न हो, इसके लिए वह चौकस रहेगा।

मनोज झा के क्या थे तर्क?

राजद सांसद मनोज झा ने अपनी याचिका में एसआईआर को लोगों को मताधिकार से वंचित करने की सुनियोजित कोशिश बताया था. कोर्ट ने हालांकि प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं दिया गया है जिससे यह लगे कि यह प्रक्रिया व्यापक स्तर पर लोगों को नुकसान पहुंचा रही है. यह मामला अब आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध रहेगा, लेकिन फिलहाल एसआईआर का काम पूरे देश में निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

संक्षिप्त ख़बरें

UP के अस्पताल की शर्मनाक करतूत! पैसा न चुकाने पर 5 घंटे गिरवी रखी लाश, 25000 देने पर सौंपी, 1.14 लाख का बनाया बिल; बिकी 50 डिसमिल जमीन

झांसी- गेट नंबर चार के पास स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान घायल युवक दिनेश कुशवाहा (27) की मौत के बाद परिजनों के साथ बेहद शर्मनाक व्यवहार हुआ। अस्पताल ने इलाज के नाम पर पहले 1.07 लाख रुपये वसूल किए, जबकि युवक की मौत के बाद अतिरिक्त 77 हजार रुपये जमा करने की मांग की। परिजनों के पास पैसे न होने के कारण शव लेने के लिए कई घंटे संघर्ष करते रहे।

घटना के अनुसार, दिनेश 19 नवंबर को बाइक से बहन से मिलने अपने परौल स्थित गांव जा रहे थे। बरौदिया गांव में मिट्टी के ब्रेकर से उनकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई और सिर में गंभीर चोट आई। हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन एंबुलेंस चालक ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी।

प्रारंभ में 37 हजार रुपये जमा कराए गए, बाद में 6 दिन में 60 हजार रुपये की दवाइयां मंगाई गई। मंगलवार शाम दिनेश की मौत हो गई। अस्पताल ने कुल बिल 1.14 लाख रुपये का बनाकर शेष 77 हजार रुपये की मांग की। परिजन के पास पैसा न होने के कारण अस्पताल ने शव देने से इनकार कर दिया। गांव से लोग पहुंचे और 25 हजार रुपये की मदद देने के बाद ही शव परिजनों को सौंपा गया। नवाबाद थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

परिवार का इकलौता कमाने वाला था मृतक

परिजन बताते हैं कि दिनेश परिवार का इकलौता कमाने वाला था। इलाज के लिए घर की 50 डिसमिल जमीन भी बेचनी पड़ी। पत्नी मनीषा और दो छोटे बच्चे अब बिना सहारे रह गए हैं। परिवार का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही और वसूली ने उनके जीवन पर गहरा संकट ला दिया।

सीईसी ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाते रहे राहुल गांधी, उधर अंतरराष्ट्रीय संस्था ने थमा दिया सर्टिफिकेट, बनेंगे IIDEA के चेयरमैन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त(सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है. उन पर तरह तरह के आरोप तक लगाए गए, उन्हीं ज्ञानेश कुमार अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित चुनावी संस्था की कमान संभालने जा रहे हैं. 3 दिसंबर को वे स्टॉकहोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (IIDEA) के चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे. पूरा 2026 साल वे इस संस्था की अध्यक्षता करेंगे.

भारत आईआईडीईए के संस्थापक सदस्यों में से एक है. मौजूदा समय इसके 35 सदस्य देश हैं. अमेरिका और जापान पर्यवेक्षक हैं. दुनिया भर में निष्पक्ष और मजबूत चुनाव कराने के लिए यह सबसे बड़ा मंच माना जाता है. अभी तक यह पद स्विट्जरलैंड के पास था था, अब बारी भारत की है. चुनाव आयोग ने इसे 'भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और इनोवेशन की ग्लोबल मान्यता' बताया है.

आयोग का कहना है कि ज्ञानेश कुमार भारत के 90 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अनुभव को इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर लेकर जाएंगे. वे चुनावी सुधारों, तकनीक के इस्तेमाल और निष्पक्षता के नए मानक तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे.

विपक्ष लगातार उठा रहा है सवाल

पिछले कई महीनों से कांग्रेस, तृणमूल, सपा समेत तमाम विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) में धांधली और ईवीएम को लेकर आरोप लगा रहे हैं. विपक्ष का दावा है कि कुछ राज्यों में लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और नए नाम जोड़े नहीं जा रहे.

3 दिसंबर को संभालेंगे पदभार

अब जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठीक वही चुनाव आयुक्त और वही संस्था को दुनिया की सबसे विश्वसनीय चुनावी संस्थाओं में से एक का तमगा मिल रहा है, तो विपक्ष के लिए यह जवाब बन गया है. चुनाव आयोग ने बयान में कहा कि यह सम्मान भारत के हर मतदाता और चुनाव कर्मी का है. हम ज्ञान, अनुभव और तकनीक साझा करके दुनिया के लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे. 3 दिसंबर को स्टॉकहोम में होने वाले समारोह में ज्ञानेश कुमार औपचारिक रूप से कुर्सी संभालेंगे.

क्या है यह संस्था

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (IIDEA) दुनिया का सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है जो लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मजबूत करने के लिए काम करता है. इसकी स्थापना फरवरी 1995 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई थी. भारत इसके 35 संस्थापक सदस्य देशों में से एक है. IIDEA चुनाव कराने वाली संस्थाओं संविधान विशेषज्ञों और लोकतंत्र से जुड़े लोगों को एक मंच देता है. यह चुनावी रिसर्च, ट्रेनिंग, तकनीकी मदद और बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करता है. हर साल इसके सदस्य देश एक चेयरमैन और दो वाइस-चेयर चुनते हैं.

प्रशांत किशोर की दुकान बंद हो गयी है, बिहार को ठेकेदार नहीं चाहिए, CM नीतीश के मंत्री का PK पर सबसे बड़ा हमला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पटना- बिहार की सियासत में इन दिनों प्रशांत किशोर बनाम एनडीए का मुद्दा फिर गरमाया हुआ है. अब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है. न्यूज़18 इंडिया के विशेष कार्यक्रम Diamond States Summit में बोलते हुए श्रवण कुमार ने पीके को 'राजनीति का ठेकेदार' बताया और कहा कि बिहार को नेता चाहिए, ठेकेदार नहीं।

प्रशांत किशोर की दुकान बंद हो गई है: श्रवण कुमार

न्यूज़18 इंडिया के विशेष कार्यक्रम Diamond States Summit में मंच से प्रतीक त्रिवेदी के सवालों का जवाब देते हुए श्रवण कुमार ने कहा- 'प्रशांत किशोर जी ठेकेदारी करते थे. पैसे लेकर राजनीतिक टीका-टिप्पणी करते थे. उनकी दुकान बंद हो गई है, अब चलने वाली भी नहीं है. 'उन्होंने दावा किया कि प्रशांत किशोर को बिहार की असलियत की जानकारी नहीं है और उनके दावे जमीन पर टिकते नहीं. मंत्री ने कहा- बिहार की जनता ठेकेदार नहीं, सेवक चाहती है. और सेवक के रूप में नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं।

श्रवण कुमार बोले- बिहार को जननेता चाहिए, ठेकेदार नहीं

कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने श्रवण कुमार से पूछा कि पीके ने दावा किया था कि एनडीए 25 सीटों पर सिमट जाएगी. इस पर मंत्री ने कहा- 'यह उनसे पूछिए, हमसे क्यों? हम तो उस दिन पटना लौटने की जल्दी में थे. महिला रोजगार योजना लॉन्च करनी थी. मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं और आठ बार चुनाव जीत चुका हूं.' उन्होंने आगे कहा कि पीके हर बार बयानबाजी करके सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती. मैंने पहले ही कहा था कि प्रशांत किशोर की दुकान बंद हो जाएगी. बिहार उन्हें नेता नहीं मानता, क्योंकि बिहार को जननेता चाहिए, ठेकेदार नहीं।

पीके अच्छी बातें करते हैं, पर ठेकेदारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती

श्रवण कुमार ने पीके की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा- 'अच्छी-अच्छी बातें जरूर करते हैं, लेकिन ठेकेदारी कितने दिन चलेगी? जनता अपने नेता को देखती है, ठेके पर चलने वाले को नहीं.' उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता और सुशासन की वजह से बिहार की जनता अभी भी एनडीए पर भरोसा करती है।

आधार कार्ड वाले घुसपैठियों को क्या दे दें वोटिंग अधिकार? SIR पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

SIR केस में आधार कार्ड फिर सवालों के घेरे में है. पैसे देकर आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं. घुसपैठियों के पास भी आधार कार्ड हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जो लोग कानूनी नागरिक नहीं हैं, उनके पास आधार कार्ड हैं, तो क्या उन्हें भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक बार फिर कहा, आधार कार्ड पूरी तरह से नागरिकता साबित नहीं करता है. इसीलिए हमने कहा कि SIR में एक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होगा. अगर किसी का नाम छूट गया है, तो उसे नोटिस देना होगा।

आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

आधार एक्ट में यह भी कहा गया है कि यह डॉक्यूमेंट नागरिकता या डोमिसाइल साबित नहीं करता है. इसका जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आधार कई तरह के फायदे पाने के लिए बनाया गया है. अगर किसी व्यक्ति को राशन लेने के लिए आधार कार्ड दिया जाता है, तो क्या उसे भी वोटर बना दिया जाएगा? मान लीजिए कोई पड़ोसी देश का नागरिक है. वह इस देश में मजदूरी करता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 एप्लीकेशन में जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स के सही होने को वेरिफाई करने का अधिकार है. इलेक्शन कमीशन कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है।

पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में SIR प्रोसेस को चुनौती देने वाले मामलों में चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है. केस करने वाले जवाब भी दे सकते हैं. इस मामले में राज्यों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं।

SIR प्रोसेस पर कपिल सिब्बल ने जताई चिंता

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि SIR प्रोसेस ने आम आदमी पर बेवजह दबाव डाला है. उन्होंने कहा, कई वोटर अनपढ़ हैं. फॉर्म भरना वोटरों की जिम्मेदारी नहीं है. कई अनपढ़ हैं. वे पढ़-लिख नहीं सकते. अगर वे फॉर्म नहीं भर सकते, तो उनके नाम हटा दिए जाएंगे. अगर नाम वोटर लिस्ट में है, तो उसे वैलिड माना जाएगा, जब तक कि राज्य कुछ और न कहे. अगर कोई नाम हटाया जाता है, तो यह एक सही और निष्पक्ष प्रोसेस से किया जाना चाहिए।

कपिल सिब्बल ने कहा, हालांकि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन यह नागरिकता के पक्ष में सबूत है. मेरे पास आधार कार्ड है. यह मेरा घर है. इस प्रोसेस में इसे छीना जा रहा है. जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि मरे हुए वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में SIR को खास तौर पर चुनौती देने वाली पिटीशन पर सुनवाई का शेड्यूल भी तय किया. बेंच ने इलेक्शन कमीशन से 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है. पिटीशनर फिर अपने जवाब दाखिल कर सकते हैं और उसके तुरंत बाद मामलों पर सुनवाई होगी।

'शब्दों की ताकत ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत'- शिवकुमार का इमोशनल पोस्ट, कर्नाटक में सत्ता को लेकर संघर्ष तेज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर खींचतान और बढ़ती दिख रही है. दोनों पक्षों की ओर से लगातार कुछ न कुछ कहा ही जा रहा है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर पार्टी आलाकमान उन्हें बुलाता है तो वे दिल्ली जाएंगे. वहीं राहुल गांधी ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मैसेज कर कहा था, 'कृप्या इंतजार करें.' लेकिन अब शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर किसी का नाम लिए बगैर पोस्ट किया कि अपनी बात पर कायम रहना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच राज्य के शीर्ष पद के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है. राज्य सरकार के पिछले हफ्ते 20 नवंबर को ढाई साल पूरे करने के बाद नेतृत्व बदलने को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं।

'शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत'

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज गुरुवार को सोशल मीडिया X पर एक इमेज के जरिए पोस्ट कर कहा, 'शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है. दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अपनी बात रखना है. चाहे वह जज हों, राष्ट्रपति हों या कोई भी, चाहे मैं ही क्यों न हूं, सभी को अपने वचन के अनुसार काम करना चाहिए. शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है. 'बढ़ते विवाद को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज गुरुवार को कहा कि वह कर्नाटक में लीडरशिप के बढ़ते मसले पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि नेता आगे के रास्ते पर बातचीत करेंगे और नेतृत्व से जुड़े मुद्दे को सुलझाएंगे. जो भी 'कन्फ्यूजन' है उसे खत्म करेंगे।

मैं सभी को बुलाऊंगा, चर्चा करूंगा: खरगे

यह पूछे जाने पर कि क्या CM सिद्धारमैया और उनके उपमुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जाएगा, उन्होंने कहा, 'हमें निश्चित रूप से उन्हें बुलाकर चर्चा करनी चाहिए. हम उन्हें बुलाएंगे, उनके साथ मंथन करेंगे और मुद्दे को सुलझाएंगे. 'समाचार एजेंसी PTI ने खरगे के हवाले से कहा, 'मैं सभी को बुलाऊंगा और उनके साथ चर्चा करूंगा. राहुल गांधी भी इसका हिस्सा होंगे, साथ ही CM और डिप्टी CM समेत अन्य लोग भी शामिल होंगे. सभी के साथ चर्चा करने के बाद फैसला किया जाएगा.' एक दिन पहले यह खबर आई थी कि राहुल गांधी ने शिवकुमार को मैसेज कर कहा, थोड़ा इंतजार करें. मैं आपके कॉल करता हूं।

2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला

मार्च 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चुनाव में जीत हासिल करने के समय भी सीएम सिद्धारमैया और उनके डिप्टी शिवकुमार के बीच पावर-शेयरिंग को लेकर घमासान मचा था. तब कथित तौर पर 2.5-2.5 साल वाले फॉर्मूले पर सहमति बनी थी. कहा जाता है कि पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को यह फॉर्मूला मंजूर था जिसमें ढाई साल बाद पावर का ट्रांसफर किया जाएगा. हाल के महीनों में इस समझौते के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री के समर्थक जहां कैबिनेट में फेरबदल किए जाने के संकेत दे रहे हैं तो वहीं उपमुख्यमंत्री के समर्थक कर्नाटक और दिल्ली दोनों जगह उन्हें प्रमोट किए जाने की लॉबिंग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल सरकार को स्कूल खोलने के निर्देश देकर कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार की पुनर्स्थापना की

भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिलने के बाद भी कई राज्यों में आधारभूत ढाँचे, जनसंख्या वृद्धि, वित्तीय बाधाओं और प्रशासनिक लापरवाही के कारण प्राथमिक शिक्षा की पहुँच प्रभावित होती रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल सरकार को प्राथमिक और लोअर प्राइमरी स्कूल खोलने के स्पष्ट निर्देश देना इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने राज्य की स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जो राज्य खुद को शिक्षाक्षेत्र में शत प्रतिशत साक्षर होने का दावा करता है, वहाँ स्कूली ढाँचे की ऐसी स्थिति बेहद चिंताजनक है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शिक्षा में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और तीन महीने के भीतर नई नीति बनाना अनिवार्य है।यह निर्णय न केवल केरल के लिए बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक दिशा-सूचक संदेश है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि शिक्षा के अधिकार को केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर लागू करने की आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी पर सुप्रीम ने चिंता जताई।सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि शत-प्रतिशत साक्षरता का दावा करने वाला राज्य भी प्राथमिक स्कूलों की कमी से जूझ रहा है, तो यह बेहद गंभीर स्थिति है। कोर्ट ने शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मूलभूत अधिकार बताते हुए कहा कि शिक्षा में कोई कमी स्वीकार नहीं की जाएगी।सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी दो बड़े मुद्दों पर रोशनी डालती है।राज्य की प्राथमिक शिक्षा के प्रति ढिलाई, और स्कूलों की पहुँच का अभाव, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। भारत में शिक्षा का अधिकार आरटीई स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, और इसके लिए पर्याप्त संख्या में स्कूल उपलब्ध होना अनिवार्य है।हर एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल होना आवश्यक है कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि केरल के कई क्षेत्रों में एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति आरटीई एक्ट 2009 के निर्देशों के सीधे उल्लंघन में आती है।आरटीई के नियम के अनुसार लोअर प्राइमरी स्कूल अधिकतम 1 किमी दूरी पर होना चाहिए।अपर प्राइमरी स्कूल अधिकतम 3 किमी के दायरे में होना चाहिए। कोर्ट ने इस अभाव को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि जब तक स्थायी स्कूल भवन उपलब्ध न हो, तब तक प्राइवेट बिल्डिंग का उपयोग कर अस्थायी रूप से स्कूल चलाए जा सकते हैं।इस तरह कोर्ट ने शिक्षा के बुनियादी अधिकार की रक्षा करते हुए व्यावहारिक समाधान भी सुझाए।बजट व्यवस्था और संसाधनों की कमी पर कोर्ट का स्पष्ट रुख है। राज्य सरकारें अक्सर शिक्षा पर बजट की कमी का हवाला देती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बजट का इंतजाम सरकार की जिम्मेदारी है, बच्चों की शिक्षा किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए।यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकिकई राज्यों में शिक्षा को लेकर बजट प्राथमिकता में नहीं होता। सरकारी योजनाएं कागजों पर रह जाती हैं।वित्तीय बाधाओं के कारण स्कूलों का निर्माण और संचालन प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश राज्य सरकारों को शिक्षा बजट में पारदर्शिता और प्राथमिकता देने का मार्ग दिखाता है।शिक्षक की कमी के मद्देनजर रिटायर्ड शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति का सुझाव भी दिया गया।कोर्ट को जानकारी दी गई कि स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया धीमी है और कई पद खाली पड़े हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया किरिटायर्ड शिक्षकों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है,ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

यह समाधान बेहद व्यावहारिक है क्योंकि रिटायर्ड शिक्षक अनुभवी होते हैं और प्रशासनिक देरी के बीच शिक्षा व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केरल का शिक्षा मॉडल और मौजूदा चुनौतियाँभी मुहफाडे खड़ी है।केरल का शिक्षा मॉडल विश्व स्तर पर सराहा जाता रहा है।वहाँ की साक्षरता दर 95% से अधिक है। सार्वजनिक स्कूलों की गुणवत्ता देश में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ रहा है।इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की कमी चौंकाती है। क्योकि नई बस्तियों में स्कूलों का अभावदिखाई दे रहा हैजनसंख्या का असमान वितरण भी बड़ा कारण है।पुराने स्कूलों का विलय या बंद होना भी दूसरा बड़ा कारण है। नई स्कूल नीति का अभाव भी शिक्षा स्तर को प्रभावित करता है।सुप्रीम कोर्ट ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तीन महीने में व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है। शिक्षा की कमी का व्यापक असर बच्चो के भविष्य पर पड़ता है।जब प्राथमिक स्तर पर स्कूल उपलब्ध नहीं होते, तो इसका असर केवल पढ़ाई पर नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक विकास पर भी पड़ता है।इससे प्रभावित होने वाले मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी है।स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती है। लड़कियों की शिक्षा पर इससे गंभीर प्रभाव पड़ता है।क्योंकि बाल श्रम की आशंका बढ़ती है। और इतना ही नही ,समाज में असमानता गहरी होती है। ग्रामीण और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसलिए कोर्ट का यह निर्देश बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने वाले दूरगामी परिणाम रखता है। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में मामला राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता और समान अवसरों पर जोर है।लेकिन यदि किसी राज्य में आधारभूत ढांचा ही उपलब्ध न हो तो नीति बेअसर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को मजबूती देगा,सभी राज्यों के लिए मिसाल बनेगा,प्राथमिक शिक्षा को नीति-निर्माण का मुख्य केंद्र बनाएगा। न्यायपालिका की सक्रियता शिक्षा सुधार में अहम भूमिका। निभाएगी।भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं।यह मामला भी उसी परंपरा का विस्तार है जहाँ अदालत बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामने आई है।न्यायपालिका का यह सख्त रुख महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों की शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, सरकारें किसी बहाने से पीछे नहीं हट सकतीं,शिक्षा का अधिकार केवल किताबों का

विषय नहीं बल्कि व्यावहारिक सच्चाई है। आने वाले समय में संभावित सुधार औरसुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल सरकार को तीन महीने में नीति बनाने का निर्देश दिए जाने के बाद अपेक्षित सुधार की कदमताल में सरकार बढ़ती नजर आएगी? क्योकि नई स्कूल नीति का निर्माणऔरजनसंख्या के आधार पर स्कूलों की संख्या तय होगी।दूरस्थ क्षेत्रों में नए स्कूल प्रस्तावित होंगे।

अस्थायी रूप से प्राइवेट बिल्डिंग का उपयोगस्कूलों के संचालन में तुरंत सुधार दिखाई देगा। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजीआएगी।अनुबंध आधारित और रिटायर्ड शिक्षकों की नियुक्ति से कमी दूर होगी।आधारभूत सुविधाओं में सुधार भी देखा जा रहा है।कक्षाएँ, शौचालय, पेयजल, डिजिटल उपकरणों की व्यवस्था मजबूत होगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारबढ़ेगी।केरल का मॉडल और अधिक मजबूत और आधुनिक बन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल केरल के लिए नहीं बल्कि पूरी भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह बताता है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार की कमी या लापरवाही स्वीकार योग्य नहीं है। बच्चों का भविष्य देश का भविष्य है, और प्राथमिक शिक्षा वह नींव है जिस पर राष्ट्र निर्माण खड़ा होता है।केरल सरकार से अपेक्षा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षा व्यवस्था को नयी मजबूती देगी और हर बच्चा अपने अधिकार, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, को प्राप्त कर सकेगा।

कांतिलाल मांडोत

अधिकारों का हनन न हो तो श्रम सुधार कानून मील का पत्थर साबित होगा

सशक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत के अपने सपने को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम सुधारों की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पचास करोड़ से अधिक श्रमिकों के स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर जीवन निर्माण की दिशा में वर्षों से चले आ रहे बेहद पेचीदे और जटिल 29 श्रम कानूनों को चार लेबर कोड में समाहित कर श्रम कानूनों को सरल बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में ही श्रम संहिता संसद से पारित हो गई थी, लेकिन पाँच वर्ष बाद एकाएक संसद में पारित चारों लेबर कोड अर्थात श्रम संहिता की अधिसूचना जारी कर देश के पचास करोड़ श्रमिकों और उनके परिवारों के चेहरों पर सुखद भविष्य की मुस्कान बिखेर दी है। निस्संदेह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही श्रमिकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा देकर 'श्रमेव जयते' योजना की शुरुआत कर देश को यह संकेत दे दिया था कि भविष्य में श्रमिकों के हितार्थ सरकार कोई बड़ा निर्णय लेगी। आजादी के साढ़े सात दशक बीत जाने के बाद पहली बार केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों को वेतन सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा देने हेतु पुराने जटिल श्रम संहिता को चार लेबर कोड मे सीमित कर नए प्रकार से श्रम कानून का निर्माण किया है। नए लेबर कोड से निश्चित ही श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की गारंटी रहेगी, महिला और पुरुष के वेतन में समानता सुनिश्चित होगी तथा हर पाँच वर्ष में न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाएगी। चार नए लेबर कोड बनाकर केंद्र सरकार ने देश के श्रमिकों को अंग्रेजी शासन काल के पेचीदे काले श्रम कानूनों के मकड़जाल से आजादी दिलाई है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिक मोदी सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। श्रम संहिता की अधिसूचना जारी होते ही विपक्ष द्वारा पर्दे के पीछे से श्रमिकों के

मन में नए लेबर कोड के प्रति कुशंकाएँ भरी जा सकती हैं और भविष्य मे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के लिए श्रमिकों को उकसाया भी जा सकता है। बहरहाल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को श्रमिकों के मन में उठने वाली शंकाओं और कुशंकाओं को जल्द ही निराकरण कर उन्हे दूर करते हुए उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि नए लेबर कोड लागू होने के बाद उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा और उन्हें अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की पूरी आजादी रहेगी। उम्मीद हे केंद्र सरकार नए लेबर कोड के संबंध मे उठने वाले विरोध के स्वरों का निराकरण कर देती हे तो निश्चित चारों लेबर कोड आजाद भारत के इतिहास में श्रम सुधार के क्षेत्र मे निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा।

अरविंद रावल

एक कवि, एक मधुशाला, और पूरी सदी पर छाया हुआ नशा

[जहाँ शब्दों में आग हो और अर्थों में मेघ—वही हरिवंश राय बच्चन]
[हरिवंश राय बच्चन: हिंदी को सिर्फ भाषा नहीं, एक नशा बना दिया]

27 नवंबर 1907। प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गाँव में, एक साधारण से कायस्थ परिवार में जन्मे नवजात की आहट किसी को नहीं बताती थी कि यह बच्चा आगे चलकर हिंदी साहित्य की तकदीर बदल देगा। परिवार ने नाम दिया–हरिवंश राय। पर समय ने उसके चारों ओर एक और पहचान बुन दी–बच्चन, और यही बच्चन आगे चलकर उन कविताओं का जनक बना, जिनमें पहली बार शब्द शराब की तरह चढ़े, जिनमें पहली बार धुएँ की लकीरें भी जीवन-दर्शन बनकर उभरीं, और जिसने निडर होकर कहा–जीवन एक मधुशाला है; जो जीना चाहता है, वह पहले पीना सीखे। परंपरागत पृष्ठभूमि से निकलकर भी बच्चन परंपरा के बंद दरवाज़ों में कैद नहीं हुए। उन्होंने शिक्षा को विद्या नहीं, दिशा बनाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए उन्होंने सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं समझा–उन्होंने अपने भीतर सोई साहित्यिक चेतना को जगाया, उसे पंख दिए, उसे उड़ान दी। उनकी यात्रा किताबों के अध्यायों तक सीमित नहीं थी; वह एक ऐसी भाव-यात्रा थी जो संवेदनाओं के अंधेरों से गुज़रती हुई आत्मानुभूति के उजालों तक पहुँचती है, जहाँ शब्द सिर्फ लिखे नहीं जाते–जिये जाते हैं। मधुशाला के बिना हरिवंश राय बच्चन की छवि ऐसे लगती है, जैसे किसी मंदिर में दीपक न जले–अधूरी, अपूर्ण, और अपने उजाले की प्रतीक्षा करती हुई। 1935 में जब 'मधुशाला' छपी, तो पूरा हिंदी जगत स्तब्ध रह गया। एक तरफ़ छायावाद के कवि फूलों-पत्तियों में प्रेम ढूँढ रहे थे, दूसरी तरफ़ एक 28 साल का नौजवान शराब, प्याला, साकी और हाला को प्रतीक बनाकर जीवन का पूरा दर्शन सुना गया। उसने लिखा - 'मृत्यु न आती यदि जीवन में, जीवन होता न इतना सुहाना।' यह पंक्ति कोई दार्शनिक की नहीं थी, यह उस युवक की थी जिसने जीवन को गिलास की आख़िरी बूंद तक चखने का फ़ैसला कर लिया था। मधुशाला कोई शराब की प्रशंसा नहीं थी, वह जीवन के अनगढ़, अनावृत, निडर सौंदर्य का उत्सव थी - नग्न, बेलौस, बेख़ौफ़। बच्चन की कविता में जो बात सबसे ज़्यादा चुभती थी, वह उसकी निर्मम ईमानदारी थी। वह कभी ढोंग नहीं करते थे। प्रेम लिखा तो ऐसा कि लगे अभी कोई आशिक़ सिगरेट का कश लेकर आह भर रहा हो - 'रात आधी खींचकर मेरा आँचल... '। दर्द लिखा तो ऐसा कि जैसे कोई अपना सीना चीरकर दिखा रहा हो। और संघर्ष लिखा तो 'अग्निपथ' लिखा - वह कविता जो आज भी हर उस लड़के की रगों में दौड़ती है जो रात-रात भर पढ़कर सुबह असफल होता है, फिर भी उठता है। 'तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी...' - यह किसी मंच पर खड़े, तालियाँ बटोरते प्रेरक वक्ता की आवाज़ नहीं थी। यह एक पिता था, जो अपने बेटे की हथेली में जीवन का सबसे कठोर, सबसे कीमती शस्त्र रख रहा था। और उस बेटे का नाम था–अमिताभ बच्चन। उन्होंने जीवन को कभी दो रंगों में नहीं बाँटा। उनके लिए जीवन न उजला था, न काला–बल्कि वह तीखी, झकझोर देने वाली धूसर रोशनी था, जहाँ हर अनुभव अपने पूरे ताप के साथ जलता है। श्यामा की मृत्यु ने उनके भीतर ऐसी दरार डाली, जो किसी को भी जीवनभर के लिए बिखरा देती–लेकिन बच्चन टूटे नहीं; उन्होंने उस टूटन को ही अपनी कविता का नया आधार बना दिया। जब तेजी सूरी से प्रेम हुआ तो प्रेम की औपचारिकताओं में नहीं बँधे। वर्षों साथ रहे–बिना परिभाषाओं, बिना सामाजिक मुहर के, और विवाह के बाद भी वही अपरिवर्तित दीवानगी, वही अनकही निकटता उनके बीच जलती रही। उनके घर की हवा में कविता पढ़कर नहीं, जीकर बसती थी। रसोई में उबलती चाय के साथ तेजी अपनी धुनें घोलतीं, और बालकनी में बच्चन साहब सिगरेट के धुएँ में ऐसे छल्ले बनाते जिनमें धीरे-धीरे नई रुबाइयों के चेहरे उभर आते–मानो जीवन खुद उनके शब्दों का शिष्य हो। बच्चन ने हिंदी को वह आवाज़ दी जो आज तक कोई दूसरा कवि नहीं दे पाया - युवा मन की बेक़ाबू, अनगढ़, तेज़तर्रार आवाज़। जब साहित्य सभ्यता, संस्कार और मर्यादा की चमक-दमक में सिमट रहा था, तब बच्चन ने कहा – 'हाँ, मैं नशे में हूँ, प्रेम में हूँ, जीवन में हूँ–और यह मेरा अभिमान है, अपराध नहीं।' उनकी हर पंक्ति में एक विद्रोह था, एक बग़ावत थी, पर इतनी सौंदर्यपूर्ण, इतनी सम्मोहित करने वाली, कि विद्रोह का ताप नहीं, उसका आकर्षण महसूस होता था। वह शराब के प्रतीकों में जीवन का सार घोलते थे, जबकि स्वयं मदिरा से कोसों दूर थे। प्रेम पर ऐसी पंक्तियाँ रचते जो दिलों में भूचाल ला दें, पर स्वयं प्रेम में पागलपन की सीमा कभी न लाँघते। और जीवन? जीवन के बारे में उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं–उसे ऐसे जिया जैसे हर दिन अंतिम हो, और हर अंतिम दिन एक नया आरंभ। आज उनकी 118वीं जयंती है, और यह आश्चर्य नहीं–मधुशाला अब भी खुली है, अब भी बह रही है, अब भी जीवित है। कहीं कोई लड़का अपनी प्रेमिका को व्हाट्सऐप पर 'जो बीत गई सो बात गई' भेजकर टूटे दिल को सांत्वना दे रहा

है। किसी जिम में कोई नौजवान 'अग्निपथ! अग्निपथ!' की गूँज के साथ डंबल उठा रहा है। किसी बार में एक बुज़ुर्ग अकेला गिलास घुमाते हुए धीमे से गुनगुना रहा है– 'मुसाफ़िर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना... '। और किसी अस्पताल के आईसीयू में कोई आख़िरी साँस लेते हुए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे याद आ रही है बच्चन की वह निर्भीक, अनश्वर पंक्ति - 'मरना तो है ही एक दिन, फिर क्यों न आज मर जाएँ हम मधुशाला में। 'हरिवंश राय बच्चन देह छोड़कर चले गए, पर उनकी कविता कहीं नहीं गई। वह अब भी हमारी नसों में दौड़ती है, हमारे साहस में उभरती है, हमारे प्रेम में पिघलती है, और हमारे संघर्ष में तलवार बनकर चमकती है। वह आज भी जीवित हैं–हर उस प्याले में जिसे कोई उठा कर जीवन को चुनौती देता है; हर उस रास्ते पर जिसे कोई अपनी आग से अग्निपथ बना लेता है; हर उस आँख में जो आँसू निगलकर भी मुस्कुराने का हौसला पाती है। क्योंकि बच्चन ने यह सिद्ध कर दिया था–असली कविता मरती नहीं; वह बस प्याले बदलती है, पर नशा वही रखती है। और मधुशाला? वह तो अभी भी खुली है, अब भी बुला रही है। चलो... एक प्याला हो ही जाए।

प्रो. आरके जैन

संपादकीय

हिंदी सिनेमा के ही-मैन का सिनेमाई सफर

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं, जो केवल अभिनेता नहीं बल्कि युग का पर्याय बन जाते हैं। धर्मेंद्र ऐसा ही एक नाम हैं–एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी सादगी, अपनी जड़ों से जुड़े चरित्र, और अपने विशिष्ट अभिनय से भारतीय सिनेमा को न केवल समृद्ध किया, बल्कि उसे जनमानस की संवेदनाओं के और करीब ला दिया। जब आज हम उनके छह दशकों से अधिक फैले फिल्मी सफर को देखते हैं, तो समझ आता है कि क्यों वे दर्शकों के लिए सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि भारतीय समाज की आकांक्षाओं, संघर्षों और सपनों के प्रतिनिधि थे। पंजाब के लुधियाना जिले के सहनेवाल गाँव से आई यह प्रतिभा किसी फिल्मों के परिवार से नहीं थी, किसी परिचय की बैसाखियों पर भी नहीं खड़ी थी। एक साधारण किसान परिवार में 8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्म सिंह देओल, यानी हमारे धर्मेंद्र, अपनी स्कूल की पढ़ाई के दिनों से ही पर्दे के सपने देखा करते थे। पर उनके पास न साधन थे, न मार्गदर्शन–सिर्फ जुनून और अदम्य इच्छाशक्ति। यही जुनून उन्हें 1960 में बंबई के उस मायावी संसार तक ले आया जहाँ असंख्य चेहरे चमकने का सपना लेकर आते हैं, पर कुछ ही सितारों में बदल पाते हैं। धर्मेंद्र उन चुनिंदा चेहरों में शामिल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी संघर्ष की आग से गुजरना पड़ा। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए मिली 51 रुपये की मामूली राशि उनके सफर का आरंभ भर थी; असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब उन्हें लगातार छोटे-छोटे किरदारों में अपने अस्तित्व को साबित करना था। परंतु फिल्म इंडस्ट्री की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच उनका धैर्य, प्रतिबद्धता और विनम्र आचरण उन्हें अलग पहचान दिलाते गए। अनपढ़, बंदिनी, आई मिलन की बेला और हकीकत जैसी फिल्मों में उनका शांत, सहज और भावपूर्ण अभिनय लोगों का ध्यान खींचने लगा। वे उन विरले अभिनेताओं में थे जिनका चेहरा पर्दे पर आते ही दर्शकों को एक भरोसे की अनुभूति देता था–एक ऐसा भरोसा कि यह कलाकार अपने किरदार के साथ न्याय करेगा। 1966 में आई फूल और पत्थर ने उस भरोसे को स्टारडम में बदल दिया। यह फिल्म न केवल उनके करियर का मोड़ बनी, बल्कि उस दौर के एक्शन-हेरो की परिभाषा को भी बदल गई। धर्मेंद्र ने यह सिद्ध कर दिया कि ताकतवर शरीर और खुरदरे बाहरी व्यक्तित्व के पीछे भी एक संवेदनशील, भावनाओं से भरा इंसान हो सकता है। वे रोमांस, ड्रामा, एक्शन–हर जॉनर में सहजता से ढल जाते थे। उनकी आँखों से झलकने वाली शरारत, मुस्कान में छिपी मासूमियत और संवाद अदायगी की सादगी ने उन्हें करोड़ों दर्शकों का चहेता बना दिया। 1970 का दशक उनका स्वर्णिम युग था। यह वही दौर है जब शोले में वीरू के रूप में उन्होंने एक ऐसा किरदार रचा, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्थायी अमरता पा चुका है। वीरू की प्रेमालाप की निश्छलता हो, गैब्बर के आतंक के सामने भी न हार मानने वाला साहस हो, या दोस्ती निभाने की अटूट प्रतिबद्धता–धर्मेंद्र ने इस किरदार को इस तरह जिया कि वह पीढ़ियों तक दर्शकों की स्मृतियों का हिस्सा बन गया।

चुपके चुपके में उनका हास्य अभिनय, मेरा गांव मेरा देश का एक्शन, यादों की बारात और सीता और गीता का पारिवारिक-भावुक आयाम–इन सबने उन्हें केवल एक ही-मैन नहीं, बल्कि बहुआयामी कलाकार के रूप में स्थापित किया। 1980 के दशक में भी उनका जलवा कम नहीं हुआ। 1987 में उनकी 11 फिल्मों का रिलीज़ होना और उनमें से 7 का सुपरहिट होना आज भी एक रिकॉर्ड है–एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने उनके अपार जनसमर्थन को प्रमाणित किया। यह वह समय था जब नए सितारे उभर रहे थे, पर धर्मेंद्र की लोकप्रियता का सूरज अविचल चमक रहा था। दर्शकों के लिए वे उस नायक की छवि थे, जो मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानता, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है और जिसे देखकर साधारण लोग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति का सपना देख सकते थे। लेकिन धर्मेंद्र केवल अभिनेता नहीं रहे; वे एक सफल निर्माता भी बने। अपने पुत्र सनी देओल को लेकर बनी फिल्म घायल उनकी प्रोडक्शन दृष्टि और सिनेमा के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार और कई फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित हुई। उनका परिवार–सनी, बॉबी और हेमा मालिनी–आज भी भारतीय सिनेमा में सक्रिय योगदान दे रहा है, और यह सब कहीं न कहीं धर्मेंद्र की उस मजबूत नींव का परिणाम है जिसे उन्होंने अपने परिश्रम से स्थापित किया। धर्मेंद्र का जीवन चाहे फिल्मों में रहा हो, पर उनका हृदय हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। वे जमीन से जुड़े, विनम्र और अत्यंत भावुक

व्यक्ति के रूप में पहचान रखते थे। उनके व्यक्तित्व में किसी नायक की बनावटी चमक नहीं थी; उसमें एक किसान का ईमान था, एक सपने देखने वाले युवक का उत्साह था, और एक कलाकार की संवेदनशीलता थी। यही कारण है कि दर्शकों ने उनसे केवल किरदारों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी प्रेम किया। 24 नवम्बर 2025 को उनका निधन भारतीय फिल्मजगत के लिए अपूरणीय क्षति बनकर आया। यह खबर केवल उद्योग ही नहीं, बल्कि देशभर के उन लोगों को भी व्यथित कर गई जिनके जीवन में धर्मेंद्र किसी न किसी रूप में प्रेरणा, मनोरंजन और भावनात्मक संबल के रूप में उपस्थित थे। परंतु कलाकारों की मृत्यु केवल शारीरिक होती है–उनकी रचनाएँ, उनके किरदार, उनकी आवाज़ और उनकी स्मृतियाँ समय से परे जीवित रहती हैं। धर्मेंद्र भी इसी अमरता के अधिकारी बने। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तो यह सिर्फ एक अभिनेता की सफलता की कहानी नहीं लगती; यह एक साधारण परिवार से आए युवक के सपनों की विजयगाथा है। यह उस भारत की कहानी है जिसमें मेहनत, ईमानदारी और लगन से सब संभव है। धर्मेंद्र न केवल फिल्मों में हीरो थे, बल्कि जीवन में भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के प्रतीक थे। उनका सफर हिंदी सिनेमा के इतिहास को भले ही गौरव देता है, पर उससे कहीं अधिक उन अनगिनत सपनों को हिम्मत देता है जो छोटे-से गाँवों से उठकर बड़ी दुनिया को जीतना चाहते हैं। धर्मेंद्र आज भले हमारे बीच न हों, पर वे अपनी फिल्मों, अपने संवादों, अपने सरल व्यक्तित्व और अपनी अनूठी विरासत के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे। वास्तव में, वे उन दुर्लभ कलाकारों में से हैं जिनका सितारा जीवन के बाद भी चमकता रहता है–और हिंदी सिनेमा के आकाश में यह चमक अनंतकाल तक बनी रहेगी।

प्रो. आरके जैन

राम ध्वज के नीचे जन्म लेता नया भारत

राम मूल्य और मोदी संकल्पः 'गुलामी-मुक्त भारत' रोडमैप मैकॉले की परछाई से राम राज्य की ओरः भारत का नया रोडमैप

अयोध्या की सुबह, सरयू की लहरों के साथ जैसे राम की वापसी का गान गा रही थी। सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी, और वहां खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी– साधारण वेश में, लेकिन आंखों में अटूट संकल्प लिए। हाथों में 22 फुट ऊंचा 'धर्म ध्वज', भगवा रंग (सूर्य, 'ओम' और कोविदार वृक्ष का प्रतीक) में लिपटा, जैसे राम के न्याय, त्याग और सत्य का प्रतीक है। जैसे ही ध्वज हवा में लहराया, लाखों दिल धड़क उठे। यह क्षण केवल एक उत्सव नहीं था; यह था गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का बिगुल। मोदी जी की आवाज, शांत लेकिन गरजती हुई, बोलीः 'सदियों पुराने घाव अब भर रहे हैं।' और फिर वह ऐतिहासिक वादा–अगले दस वर्षों में भारत को 'गुलामी की मानसिकता' से पूरी तरह आजाद करना। यह रोडमैप कोई कागजी योजना नहीं, बल्कि एक जीवंत क्रांति है, जो हर भारतीय को राम की तरह संघर्षशील बनाएगी, अपनी जड़ों से जुड़ाएगी। अयोध्या, जहां राम मंदिर अब खड़ा है, वहां 45 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं–यह संख्या नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, जो बताता है कि राम सिर्फ मंदिर में नहीं, हर दिल में बसते हैं। गुलामी की मानसिकता–यह क्या है? वह अदृश्य जहर जो 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने बोया, शिक्षा के नाम पर हमें अपनी संस्कृति से दूर करना, हमें पश्चिमी सोच का गुलाम बनाना। आज भी वह जहर हमारे विचारों में बहता हैः अपनी भाषा को कमतर समझना, पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, राम को सिर्फ कहानी मानना। मोदी जी ने इसे सीधे चुनौती दी– 'हमारी आजादी अधूरी है, क्योंकि मन अभी गुलाम है।' दस वर्षों का यह रोडमैप इसी जहर को निकालने का है। पहला पड़ावः सांस्कृतिक जागरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मैकॉले की छाया से मुक्त करना, स्कूलों में रामायण को जीवंत बनाना। जहां बच्चे न सिर्फ पढ़ें, बल्कि राम के गुणों–धैर्य, दया, नेतृत्व–को जीएं। जैसे राम ने वनवास में भी संकल्प नहीं छोड़ा, वैसे ही हर बच्चा अपनी जड़ों से मजबूत बने। यह होगा राष्ट्र का नया निर्माण, जहां भारत

अपनी विरासत पर गर्व करे, न कि किसी विदेशी सोच पर। मोदी जी ने कहा, 'राम व्यक्ति नहीं, मूल्य हैं–जो हमें दिशा देते हैं।' और यह मूल्य अब भारत की अर्थव्यवस्था में भी दिखेंगेः आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जल्द तीसरी बनेंगे। लेकिन असली जीत तब होगी जब हम आर्थिक स्वावलंबन को राम के स्वदेशी से जोड़ें। यह रोडमैप सरल है, लेकिन अप्रतिम–क्योंकि यह राम राज्य के सपने पर टिका है। राम राज्य में क्या था? न्याय की धारा हर घर तक, पर्यावरण का सम्मान जहां जटायु और गिलहरी भी योगदान दें, समाज जहां कोई भेदभाव न हो। मोदी जी ने अयोध्या को इसी का प्रतीक बताया– 'यहां का सामूहिक प्रयास विकसित भारत 2047 का रोडमैप है।' दस वर्षों में, हमें 'मेक इन इंडिया' को राम की उद्यमिता से सशक्त करना है। युवाओं को स्टार्टअप्स में राम सेतु जैसा पुल बनाना सिखाना–छोटे प्रयासों से बड़ा लक्ष्य। अयोध्या, अब हजारों तीर्थों का मॉडल बनेगी। पर्यटन से अर्थव्यवस्था बूम करेगी, लेकिन साथ में सांस्कृतिक दूतावास भी। युवाओं की भूमिका यहां सबसे दमदार है। आज की पीढ़ी, जो सोशल मीडिया पर खोई है, उसे राम की कहानी से जोड़ना। मोदी जी का आह्वान– 'युवा उठो, राम के धनुष को उठाओ।' दस वर्षों का दूसरा चरणः युवा सशक्तिकरण। सोशल मीडिया पर राम कथा वायरल करना, एनजीओ से ग्रामीण भारत में राम मेलों का आयोजन। जैसे राम ने लक्ष्मण और हनुमान के साथ टीम बनाई, वैसे ही युवा एकजुट हों। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं–व्यावहारिक कदम, जैसे डिजिटल रामायण ऐप्स, जहां युवा राम के संघर्ष से प्रेरणा लें और अपनी जिंदगी में लागू करें। अनुपम बात यह है कि यह रोडमैप समावेशी है। राम राज्य में कोई भेदभाव नहीं–दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सबका साथ। मोदी जी ने कहा, 'राम के कण-कण में भारत, भारत के कण-कण में राम।' दस वर्षों का तीसरा चरणः सामाजिक सद्भाव। जाति की दीवारें राम नाम से तोड़ना, त्योहारों को साझा बनाना। कल्पना कीजिए, एक भारत जहां त्योहार राम की तरह साझा हों, जहां गिलहरी जैसा छोटा योगदान भी बड़ा बने। लेकिन चुनौतियां हैं–विपक्ष की आलोचना, सेकुलरिज्म के नाम पर सांस्कृतिक अस्मिता को दबाना। मोदी जी का जवाब साफ– 'संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास।' यह दस वर्ष 2047 तक विकसित भारत की नींव रखेंगे, जब आजादी के सौ साल पूरे होंगे। तब भारत न सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि विश्व गुरु भी–राम के आदर्शों से। अयोध्या का यह ध्वजारोहण 500 साल पुराने संकल्प की पूर्ति है, लेकिन नई शुरुआत भी। सदियों पुराने घाव भर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर अब सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, बल्कि एकता का प्रतीक है। सरल शब्दों में कहें तो यह वादा हर भारतीय का है। मोदी जी की वाणी जैसे राम की वाणी–शांत, लेकिन अटूट। 'हमारी विरासत पर गर्व करो, गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो जाओ।' युवाओं, सुनो–यह तुम्हारा समय है। राम के जैसे संघर्ष करो, लक्ष्य पर नजर रखो। दस वर्षों में, हम मैकॉले की किताबों को रामायण से बदल देंगे। पर्यावरण संरक्षण से लेकर सामाजिक न्याय तक, सब राम राज्य से प्रेरित। अयोध्या की सरयू आज गवाह है–राम लौट आए हैं, और उनके साथ एक नया भारत जाग रहा है। यह यात्रा शुरू हो चुकी, अब रुकना नहीं। राम के नाम पर, भारत के नाम पर–जय सिया राम!

प्रो. आरके जैन

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

बनी टीम ने कुकुरी को 57 रन से हराया

बनी टीम के अंकित यादव ने लगाई हैट्रिक, मैन ऑफ द मैच बने

भरावन (हरदोई)। बीवीएम इंटर कॉलेज के मैदान पर चल रहे तृतीय क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मैच में बनी टीम ने कुकुरी टीम को 57 रनों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। बनी टीम के कप्तान मयंक सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। ओपनर बल्लेबाज अंकित यादव ने धुंआधार 13 रन की पारी खेल टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। बनी टीम 8.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 82 रन का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुकुरी टीम शुरुआत बेहद खराब रही। लगातार विकेट गिरते गए। और 10.3 ओर में 24 रन बनाकर टीम सिमट गई। बनी टीम के बॉलर अंकित यादव ने हैट्रिक लगाकर कुकुरी टीम की कमर तोड़ दी। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। आयोजक कर्नल आदित्य सिंह ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड सौंपा। इस दौरान शैलेन्द्र सिंह, राजू पांडे, विकास पांडे, विष्णु चौहान, डॉ शैलेंद्र बाजपेई, जीतू पांडे, मिलन मिश्र, सुबोधकांत मिश्र, सचिन पांडे, राकेश शुक्ल सहित दर्शक मौजूद रहे।

आयुष्मान कार्ड कैम्प आयोजन 25 दिसंबर तक

रायबरेली, नोडल अधिकारी आयुष्मान डॉ अशोक कुमार रावत ने बताया है कि पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु आयुष्मान कार्ड कैंप का आयोजन प्रदेश भर में दिनांक 25 नवम्बर 2025 से 25 दिसम्बर 2025 तक चलाया जायेगा। इस विशेष अभियान के तहत जिले में 5,88,382 आयुष्मान बनाने के लक्ष्य है।जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी इस अभियान के नोडल बनाये गये है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रदिदिन अभियान की मोनिटरिंग एवं अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन कर आयुष्मान कार्ड प्रगति को बढाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ब्लाक स्तर पर बीडीओ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक को तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान को अभियान का नोडल बनाया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 नवीन चंद्रा द्वारा अवगत कराया गया कि जिला चिकित्सालय (पुरुष एवं महिला), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर,स्वास्थ्य केन्द्रों,पंचायत भवन, कोटेदार की दुकानों पर आशा, ए.एन.एम, सी.एच.ओ, आयुष्मान मित्रों एवं पंचायत सहायकों के माध्यम से कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे 7 नोडल अधिकारी -आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ0 अशोक रावत द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद 62% आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रदेश में 17वें स्थान पर है। मुख्य सचिव (उ0प्र0)शासन के निर्देशानुसार समस्त शेष बचे लाभार्थियों एवं 70+ श्रेणी के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु आवश्कतानुसार कैंप के अतिरिक्त डोर टू डोर वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा जिससे जनपद के लक्ष्य को अभियान के दौरान पूर्ण किया जा सके।

महिला सहायता व सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का विशेष अभियान चलाया गया

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र में महिला सहायता और सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान, मिशन शक्ति प्रभारी महिला उपनिरीक्षक गौरव कुमारी, महिला उपनिरीक्षक शुचि सावंत, और महिला आरक्षी पूनम गोंड ने मुमताज स्कूल में भ्रमण किया और शिक्षकगण एवं छात्राओं को महिला सुरक्षा से संबंधित सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरः 102, 108, 112, 1090, 181, 1930 इसके अलावा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और साइबर अपराध से सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी भी दी गई। छात्राओं को 'गुड टच' और 'बैड टच' की पहचान के बारे में शिक्षित किया गया और आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के महत्व पर प्रेरित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों, और वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को सुरक्षा, सहायता, और अधिकारों के प्रति सजग बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल 'मिशन शक्ति' के बारे में भी जानकारी दी गई।

कृष्ण स्वरूप अग्रवाल सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बाल मेले का भव्य किया गया आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवा/सीतापुर आज कृष्ण स्वरूप अग्रवाल सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अमर नगर बिसवां सीतापुर में बाल मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन विद्यालय अध्यक्षा रेनू मेहरोत्रा एवं विद्यालय प्रबंधक सुरेंद्र पाल सिंह द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के गणमान्य सदस्य गण विवेक कुमार गुप्ता गीता गुप्ता , गुरुमीत कौर , उत्साह राजवंशी, तुलसी राजवंशी , , एकता गुप्ता , अंजली राजवंशी , उमंग राजवंशी , प्रधानाचार्या अल्पना अवस्थी सहित समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा, जैसे ही फीता काटा गया, पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट और बच्चों की आनंदभरी आवाज़ों से गूंज उठा। बाल मेले में छात्रों ने अपनी रचनात्मकता और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार की दुकानें लगाईं जिनमें खाद्य-पदार्थों, दक्षिण भारतीय व्यंजन, चाट-पकौड़ी, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, हस्तनिर्मित वस्तुएँ, सजावटी सामान, ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी के मॉडल, रंगोली डिज़ाइन जैसे कई आकर्षक स्टॉल शामिल थे। कई छात्रों ने खेलों की दुकानें भी लगाईं जिनमें 'रिंग गेम', 'बलून शूट', 'डाइस गेम' और 'लकी ड्रॉ' जैसे मनोरंजक खेलों में अभिभावकों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हर स्टॉल पर बच्चों ने ग्राहकों का स्वागत बड़े आत्मविश्वास और विनम्रता से किया। इससे बच्चों में संचार कौशल, प्रबंधन क्षमता और उद्यमिता के गुण विकसित होते दिखाई दिए। उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं और व्यंजनों को देखकर अभिभावक और अतिथि अत्यंत प्रभावित हुए। मेले में विज्ञान प्रदर्शनी और चित्रकला प्रदर्शनी भी विशेष आकर्षण रहीं। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने अपने नवाचारों को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया, वहीं चित्रकला प्रदर्शनी में बच्चों की कल्पनाशक्ति और कला कौशल देखते ही बनता था। साथ ही विद्यालय के मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें नृत्य, समूहगीत, नाटक व कविता पाठ जैसे प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। विद्यालय प्रधानाचार्या अल्पना अवस्थी ने अपने संबोधन में कहा कि बाल मेला बच्चों को सीखने, अनुभव प्राप्त करने और अपनी प्रतिभा को निखारने का एक

व्यावहारिक मंच प्रदान करता है। इससे बच्चों में टीमवर्क, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षकों तथा अभिभावकों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय द्वारा श्रेष्ठ स्टॉल, श्रेष्ठ प्रस्तुति और श्रेष्ठ नवाचार की श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। मेले का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। यह दिन बच्चों के लिए मनोरंजन, सीख और नए अनुभवों से भरपूर रहा, जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे।

हमारे सविधान में सभी धर्मो एवं जातियों को समान अधिकार दिये गये-प्राचार्य

लखनऊ। 76वें संविधान दिवस की पावन बेला पर महाविद्यालय में संविधान दिवस के अवसर सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें प्राचार्य सहित शिक्षक, छात्र-छात्राओं एवं कर्मचारियों उपस्थित हुए। कई शिक्षकों ने अपने-अपने विचार रखे तथा सविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0 सुभाष चन्द्र पाण्डेय ने छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए संविधान की महत्ता के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे देश का संविधान सभी देशों के संविधान से अलग है हमारे सविधान में सभी धर्मो एवं जातियों को समान अधिकार दिये गये हैं तथा कार्यक्रम का संयोजन इतिहास विभाग के सहायक आचार्य जागेश्वर प्रसाद सिंह ने किया। कार्यक्रम के अन्त में समस्त शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं ने एक स्वर में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया और संविधान तथा राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों की शपथ ली।

जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने धान क्रय केंद्रों पर किया औचक निरीक्षण

● किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए दिए कठोर निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली। महराजगंज क्षेत्र में बुधवार को जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने मंडी समिति परिसर में संचालित धान क्रय केंद्रों तथा टूक साधन सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का बारीकी से जायज़ा लिया और केंद्र पर मौजूद किसानों से सीधे संवाद स्थापित करते हुए खरीद व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की डीएम ने किसानों से धान खरीद की पूरी प्रक्रिया–तौल, गुणवत्ता परीक्षण, रिकॉर्डिंग, बोरे उपलब्धता, और केंद्र पर अन्य सुविधाओं–के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को निर्धारित दर पर तौल हो रही है तथा सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी सुविधाएँ बिना किसी अवरोध के उपलब्ध कराई जा रही हैं कई किसानों ने भुगतान व्यवस्था के संबंध में सवाल उठाए, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि धान खरीद का भुगतान निर्धारित समयसीमा के भीतर हर

हाल में किसानों के बैंक खातों में पहुँचना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भुगतान में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिलाधिकारी माथुर ने क्रय केंद्र पर रखे तौल उपकरणों, भंडारण व्यवस्था तथा रिकॉर्ड रजिस्टरों की भी जांच की। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और किसानों को किसी भी स्तर पर परेशान नहीं किया जाएगा। यदि केंद्रों पर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो किसान सीधे सक्षम अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं अंत में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता और सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान बेच सकें। उन्होंने यह भी कहा कि औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार और गति बनी रहे।

खंड शिक्षा अधिकारी बछरावां इंदिरा देवी के नेतृत्व में संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बछरावां/रायबरेली विकास क्षेत्र बछरावां की बीआरसी सभागार में खंड शिक्षा अधिकारी बछरावां इंदिरा देवी के नेतृत्व में संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी बछरावां द्वारा संविधान की पुस्तक एवं इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा उपस्थित आरपी एवं सभी शिक्षकों द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। शिक्षक आशीष कुमार गौतम एवं उमेश कुमार द्वारा भारत के संविधान निर्माण, महत्व एवं इसमें निहित भारत के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी के द्वारा संविधान की उद्देशिका वाचन किया गया तत्पश्चात आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदया द्वारा अपने उद्बोधन में संविधान के निर्माण एवं निर्माण समिति में सहयोग प्रदान करने वाले सभी महान व्यक्तित्व को स्मरण करते हुए उन्हें आभार प्रकट किया गया तथा कार्यक्रम में उपस्थित

सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई और भारत के सुयोग्य नागरिक बनकर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। इसके पश्चात उपस्थित सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को संविधान की पुस्तक भेंट की गई। इस कार्यक्रम में ए आर पी मृत्युंजय सिंह, शिक्षिका प्रमिला, मीनू जयसवाल, सुषमा वर्मा, सारिका सिंह, ज्योति वर्मा, शीलू रानी, अमन शुक्ला, चंदन सोनकर, रामप्रकाश, रामदयाल, दीप कुमार, पवन यादव, रविंद्र दिवाकर, प्रमोद मित्तल, तेज नारायण, अजय सिंह पटेल, दिनेश कुमार, डीजे गुड्डू, आदि अनेकों शिक्षक उपस्थित रहे।।

लखनऊ में मुद्रा लोन स्वीकृत कराने के नाम पर तीन लाख ठगे, साइबर ठग के जाल में फंसा डॉक्टर

लखनऊ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण स्वीकृत कराने का झांसा देकर जालसाज ने महिला से तीन लाख रुपये ठग लिए। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस छानबीन में जुटी है। उधर महानगर में साइबर जालसाज ने एक डाक्टर को ठगी का शिकार बनाया। इंदिरानगर के बी ब्लाक निवासी रंजना सिंह के मुताबिक, कुछ माह पहले कानपुर निवासी चंदन शुक्ला से मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत कराने का भरोसा दिलाया। इसके बदले उसने तीन लाख रुपये की मांग की। रंजना सिंह के मुताबिक, परिवार की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए उन्होंने यह रकम बड़ी मुश्किल से जुटाई और आरोपित के बैंक खाते में आनलाइन ट्रांसफर कर दी। रंजना के मुताबिक उनकी दो बेटियां बाहर पढ़ाई कर रही हैं। पति की नौकरी भी स्थायी नहीं है। ऐसे में छोटा व्यापार शुरू करने के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। रुपये लेने के बाद आरोपित मोबाइल बंद कर फरार हो गया। उधर, महानगर निवासी डाक्टर संतोष कुमार ने बताया कि 12 नवंबर को उनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंककर्मी बताया।

ओया गांव में 35 वर्षीय किसान की निर्मम हत्या से दहशत पुलिस के हाथ खाली-24 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चंदापुर/रायबरेली। चंदापुर थाना क्षेत्र के ओया गांव में एक 35 वर्षीय किसान की नृशंस हत्या ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। धारदार हथियार से की गई यह वारदात इतनी भयावह है कि ग्रामीण आज भी उस मंजर को याद कर सिहर जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी तक पहुँचने में असफल साबित हो रही है, जिससे कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं रात के अंधेरे में मौत, सुबह खेत में मिला खून से लथपथ मिला शव मृतक किसान समरजीत सिंह उर्फ विनीत सिंह (उम्र 35 वर्ष) सोमवार देर रात अपने खेत के पास बनी कोठरी में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी मंगलवार सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर निकले, तो कोठरी के अंदर उनका शव खून से लथपथ पड़ा मिला। गांव में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पूरे क्षेत्र में अफरातफरी मच गई पुलिस-प्रशासन मौके पर, कई थानों की फोर्स तैनात घटना की सूचना पर चंदापुर पुलिस, क्षेत्राधिकारी महराजगंज,एसओजी टीम और आसपास के थानों की भारी फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया मंगलवार देर शाम तक पोस्टमार्टम न हो पाने के कारण अंतिम संस्कार बुधवार सुबह लगभग 10 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कराया गया। गांव में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल अभी भी तैनात है फिर भी हाथ खाली–हथियार नहीं मिला, हत्यारे फरार सबसे बड़ी चर्चा यह है कि पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह के कड़े निर्देशों के बावजूद कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन हत्या में इस्तेमाल हथियार और हत्यारे दोनों अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ग्रामीणों में यह सवाल तेजी से उभर रहा है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के बाद भी

पुलिस के खाली हाथ क्यों है संदिग्धों से पूछताछ जारी–जल्द खुलासे का दावा चंदापुर थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। बहुत जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा गांव में दहशत, सुरक्षा पर सवाल ओया गांव और पूरे चंदापुर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आरोपी खुले घूम रहे हैं, जिससे लोगों में भय और नाराजगी बढ़ती जा रही है किसान की इस निर्मम हत्या ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

15 साल के अंश की कोचिंग जाने की राह पर मौत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद। लखनऊ- हरदोई राजमार्ग पर बुधवार को उस समय मातम पसर गया जब अहमदाबाद कटौली निवासी 15 वर्षीय अंश की जिंदगी एक तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप (डाले) की भेंट चढ़ गई। अंश, कक्षा 10 का होनहार छात्र था, जो अपने भविष्य को संवारने के लिए साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, लेकिन वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका।अंश अपने गांव से थोड़ी ही दूरी पर चांदपुर स्थित आकृति कोचिंग सेंटर जा रहा था। जब उसने कटौली गांव के पास रोड पार की, तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार डाले ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी कि अंश साइकिल समेत सड़क पर गिर गया और मौके पर ही गंभीर रूप से चोटिल हो गया।वह तो बस पढ़ने जा रहा था... क्या पता था कि आज घर से आखिरी बार निकला है।परिजनों की चीखों ने माहौल को गमगीन कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर भागे। अंश को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनते ही अंश की माता मनोज कुमारी, भाई प्रिंस और बहन प्रियंका पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

अपने कलेजे के टुकड़े को खोने के बाद, आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने न्याय की मांग करते हुए लखनऊ-हरदोई राजमार्ग को लगभग आधा घंटे तक जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि लापरवाह और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए।मौके पर पहुंची रहीमाबाद थाना पुलिस ने स्थिति संभाली। थाना प्रभारी अरुण कुमार त्रिगुणायक ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और यह सुनिश्चित किया कि

उन्हें हर संभव कानूनी मदद प्रदान की जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद ही प्रदर्शनकारी शांत हुए और मार्ग बहाल किया जा सका। पुलिस ने अंश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। एक होनहार छात्र की असमय मौत ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है और एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

संविधान दिवस पर आर्यकुल कॉलेज, सीतापुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर आर्यकुल कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी एंड रिसर्च, सीतापुर में संविधान दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया तथा संविधान के मूल सिद्धांत–न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व–के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉ. सशक्त सिंह, संकाय प्राचार्या डॉ. स्तुति वर्मा, डीन एकेडमिक श्रीमती रुचि सिंह, उपनिदेशक डॉ. आदित्य सिंह, डॉ. अब्दुल रब खान, रजिस्ट्रार रोहित सिंह, अध्यापक राजीव कुमार, ऋषभ शुक्ल,रेहान, तान्या उपाध्याय, नीलम वर्मा, मोहित यादव, साहिल सिंह, तिलक राज, अरुण सिंह, प्रीति यादव, प्रवीण, अबरार, रमा सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने संविधान को देश की आत्मा बताते हुए छात्रों से नागरिक कर्तव्यों के पालन और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।

इनकमिंग-आउटगोइंग बंद होने के 100 दिनों बाद किसी और को मिल जाएगा आपका नंबर, किस कंपनी ने नियमों में किया बदलाव?

लखनऊ। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने प्रीपेड सेवा में ग्रेस-2 (इनकमिंग-आउटगोइंग बंद) की अवधि घटाकर 100 दिन कर दिया है। पहले यह समय सीमा 165 दिन थी। यानी अब 100 दिनों तक रीचार्ज न कराने पर आपका नंबर पूरी तरह से बंद कर किसी और को आवंटित कर दिया जाएगा। यह संशोधन 27 नवंबर से प्रभावी होगा। बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक जफर इकबाल ने बताया कि 225 रुपये के सिल्वर जुबली प्लान में एक माह तक प्रतिदिन ढाई जीबी डेटा के साथ 100 एसएमएस और असीमित कालिंग की सुविधा दी जा रही है। 599 में प्रतिदिन तीन जीबी हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कालिंग के साथ 84 दिन की वैधता है। 199 रुपये के प्लान में असीमित कालिंग, दो जीबी प्रतिदिन डेटा के साथ 28 दिन वैधता मिलेगी। 319 के रीचार्ज पर अनलिमिटेड वाइस कालिंग के साथ 10 जीबी डेटा और 60 दिनों वैधता मिलेगी। 485 के प्लान में अनलिमिटेड वाइस के साथ दो जीबी प्रतिदिन डेटा मिलेगा। इसकी वैधता 72 दिन है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मृतक शिक्षामित्र के परिवार की मदद को सौंपा ज्ञापन

● बेटे को कोई सरकारी नौकरी तथा एक करोड रुपए की सहायता देने की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद, लखनऊ। मलिहाबाद में एसआईआर फॉर्म के दौरान अधिकारियों के दबाव से ब्रेन हेमरेज के कारण हुई शिक्षामित्र की मौत के मामले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से बुधवार को एसडीएम मलिहाबाद को डीएम को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में यह दर्शाया गया है कि मृतक शिक्षा मित्र विजय वर्मा को एसआईआर फॉर्म के लिए दबाव बनाया गया था जिस पर उन्हें अधिकारियों द्वारा दबाव में धमकी दी गई थी कि अगर समय पर कार्य न पूरा हुआ तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिसके चलते वह ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए और उनकी इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई।

कांग्रेस कमेटी का कहना है कि विजय वर्मा की मौत से उनकी पत्नी और उनके बेटे की आर्थिक स्थिति काफी दयानी हो चुकी है इसलिए उनके बेरोजगार बेटे हर्षित को कोई एक सरकारी नौकरी तथा पत्नी संगीता को एक करोड रुपए की

मदद मिलनी चाहिए। एसडीएम को शिवकुमार गौतम पूर्व जिला उपाध्यक्ष/प्रभारी विधान सभा मलिहाबाद, अजय कुमार जिला उपाध्यक्ष, परवेज रमजी खान जिला महासचिव, आकिल खान ब्लॉक अध्यक्ष मलिहाबाद, हबीबुर्रहमान सिद्दीकी उर्फ छोटे मियां पूर्व ब्लाक अध्यक्ष मलिहाबाद, श्याम कुमार ब्लाक महासचिव ने यह ज्ञापन सौंपा है। इससे पूर्व शिक्षामित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष बचनेश कुमार विजय गुप्ता, विनोद सिंह सहित शिक्षामित्रों ने परिवार को मदद दिलाने के लिए भी एसडीएम मलिहाबाद को ज्ञापन सौंपा था लेकिन अभी तक परिवार को किसी भी तरह का कोई आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है जिससे शिक्षामित्रों में भी इसको लेकर आक्रोश व रोष व्याप्त है।

गायत्री शक्तिपीठ पर उल्लास पूर्वक मनाया गया राम विवाह का कार्यक्रम

बस्ती। बस्ती जिले के गायत्री शक्तिपीठ पर राम विवाह का कार्यक्रम आज अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी 25 नवंबर 2025 मंगलवार को गायत्री शक्तिपीठ परिसर में उल्लास पूर्वक सभी परिजन भाइयों - बहनों द्वारा मनाया गया। महिला मंडल की प्रमुख रेनू मिश्रा व उनकी सहायिका प्रतिमा सिंह की संयोजन में नगर की सभी महिलाओं द्वारा राम जानकी की झांकी बनाकर मांगलिक गीत,भजन आदि गाया गया। गायत्री शक्तिपीठ के सहायक प्रबंध ट्रस्टी राम चंद्र शुक्ल और वरिष्ठ परिव्राजक/ट्रस्टी राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा की ऋषि परंपरा में हमारे पर्व त्यौहार एवं संस्कार तथा जन्मदिन विवाह दिवसोत्सव के माध्यम से जनमानस को पारस्परिक प्रेम , सहयोह , सेवा की प्रेरणाये मिलती हैं। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद वितरण तथा सामूहिक सहभोज (भंडारा) का भी आयोजन किया गया। जिसमे सैकड़ो लोगो ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जगदम्बिका पांडेय,सर्वेश श्रीवास्तव,के के पांडेय,विशाल त्रिपाठी, श्याम पांडेय, स्वामी दयाल, रेनू मिश्रा, प्रतिमा सिंह, शिखा मिश्रा, रघुनन्दन, रवि, शारदा, सीमा, वंदना, अनुजा, संजय, किरन, संगीता, नम्रता, अपराजिता, रश्मि, राशि, मंजू, अंजू, अभिसारिका, श्रुति, सोनी, गितेश्वरी आदि सैकड़ो लोग उपस्थित रहे।

संविधान दिवस पर चित्रकूट में एसपी ने दिलाई संविधान की प्रस्तावना की शपथ

● पुलिस कार्यालय व जनपद के विभिन्न इकाइयों में अधिकारियों-कर्मचारियों ने ली शपथ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चित्रकूट। संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को जनपद में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पुलिस कार्यालय में नियुक्त सभी अधिकारी-कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान को याद करते हुए संविधान की मूल भावना, अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तृत जानकारी दी। शपथ ग्रहण के बाद एसपी ने कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संविधान केवल

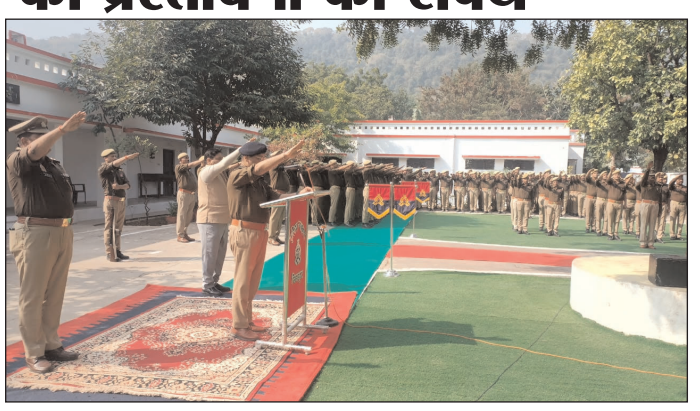

एक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की आत्मा है जो सभी को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की राह दिखाता है। संविधान दिवस पर जनपद के अन्य अधिकारियों ने भी अलग-अलग इकाइयों में शपथ दिलाई।अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने पुलिस लाइन में अधिकारी-कर्मचारियों को शपथ दिलाई।क्षेत्राधिकारी राजापुर राज कलम ने सीओ कार्यालय राजापुर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न कराया।क्षेत्राधिकारी मऊ फहद अली ने थाना मानिकपुर में मौजूद अधिकारियों-कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह, निरीक्षक एलआईयू नागेन्द्र भूषण पाण्डेय, आईजीआरएस प्रभारी निरीक्षक नागेन्द्र नागर सहित पुलिस कार्यालय में तैनात सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। संविधान दिवस के इस अवसर पर जनपदभर में राष्ट्रनिर्माण व कर्तव्यपालन के प्रति नई ऊर्जा और जागरूकता का संदेश दिया गया।

संक्षिप्त खबरें

वृद्ध जनों के सशक्तिकरण के लिए भी वृद्धावस्था पेंशन 600 से बढ़ा कर 1500 की जाए: कैलाश तिवारी

शहडोल। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश तिवारी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश सरकारो ने तथा अन्य प्रदेश सरकारों ने महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी बहना , माझी लड़की बहन योजना, लाडो लक्ष्मी योजना, मइया सम्मान योजना, बंगारू थल्ली योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं और उनको इसका व्यापक लाभ भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं पूरे भारतवर्ष में वृद्धजनों के लिए भी चलाई जाएं। भारतवर्ष में कुल आबादी का लगभग 15 करोड़ की संख्या वृद्धि जनों की है। जो कि देश की आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है। इतनी बड़ी आबादी को इस अवस्था में बेसहारा छोड़ना उचित नहीं है। वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है जहां पर केवल 600 से गुजारा नहीं होता है। पूरे देश में वृद्धावस्था पेंशन 600 से बढ़कर न्यूनतम 2000 किया जाना, आज की सामाजिक परिस्थितियों में अनिवार्य हो चुका है। पेंशन में वृद्धि से वृद्ध जन भी सम्मानपूर्वक समाज में रह सकेंगे । 600 में जीवन यापन का कार्य किया जाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सामाजिक दायित्व का भली भांति निर्वहन किया जा रहा है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में भी शीघ्र ही कोई निर्णय लेकर देश के एक बड़े वर्ग की समस्या को दूर करें।

शहडोल में शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित किए जाने के निर्णय का स्वागत

शहडोल। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री कैलाश तिवारी ने बताया है की मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल महोदय के अभि भाषण में कहा गया है की भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शहडोल सहित मंडला, बालाघाट, खजुराहो व सागर में नए शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहडोल में शासकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय खोले जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को बधाई देते हुए कहा है कि आयुर्वैदिक महाविद्यालय खुल जाने से क्षेत्र वासियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज की अच्छी सुविधा मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्व में ही मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जैसी संस्थाओं की सौगात दे चुकी है तथा प्रस्तावित भी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त एयरपोर्ट, पासपोर्ट कार्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय शहडोल में खोले जाने की घोषणा भी विगत माह में हो चुकी है। जिसका लाभ निकट भविष्य में संभाग के निवासियों को मिलेगा।

पीएम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बैठक में बैंकों मैनेजरों को जिलाधिकारी ने लगाई फटकार

चार दिनों के भीतर ऋण स्वीकृत करने के दिए निर्देश

हमीरपुर- जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को कलैक्ट्रेट सभा कक्ष में पीएम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की गई ,जिसमें वैण्डर कल्प इन्टरप्राजेज के अभियेख दिक्षित द्वारा शिकायत करने पर जिलाधिकारी महोदय, ने बैंक मेनेजरों को चार दिवस में विद्युत उपभोक्ताओं को ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये तथा परियोजना अधिकारी यूपीनेडा को निर्देश दिये कि जो बैंक समय से ऋण स्वीकृत न करें। तो मुझे अवगत कराये हवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय, द्वारा विद्युत विभाग के उप खण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि तीन दिवस में नाम परिवर्तन एंव भार परिवर्तन करने की हिदायत दी। तथा अधिशाषी अभियन्ता परीक्षण को निर्देशित किया कि अधिकतम तीन दिन में मीटर स्थापन एंव सोलर कन्सीडर कराने को कहा गया। बैठक में आर0बी0 ओझा परियोजना प्रभारी, जनपदीय बैंक मैनेजर एंव एल.डी.एम., विद्युत विभाग से अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण एंव अधिशाषी अभियन्ता परीक्षण, उपखण्ड अधिकारी एंव जनपद के समस्त पजीकृत वैण्डरों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

Arunachal को लेकर भारत के जवाब से Xi Jinping का चेहरा तमतमाया, भारतीय कंपनियों की राह में अडंगा डालने लगा China

वैसे तो भारत-चीन संबंध पिछले एक दशक में लगातार तनाव और सहयोग के बीच झूलते रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों की घटनाओं ने एक बार फिर यह रेखांकित कर दिया है कि बीजिंग के साथ किसी भी प्रकार की साझेदारी केवल आर्थिक पैरामीटर पर नहीं चल सकती।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अरुणाचल प्रदेश की महिला को शंघाई हवाई अड्डे पर रोके जाने के विरोध में भारत की तीखी प्रतिक्रिया से चीन तिलमिला उठा है जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव एक बार फिर उभर कर सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि ताज़ा घटनाओं ने भारत-चीन संबंधों के दो सबसे संवेदनशील क्षेत्रों- आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय-संप्रभुता, को एक साथ सुर्खियों में दिया है। एक ओर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग चीन की नीतिगत अस्पष्टताओं और तकनीकी सहयोग में बाधाओं से परेशान है; दूसरी ओर शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को 'अवैध पासपोर्ट' के नाम पर रोके जाने संबंधी घटनाक्रम ने कूटनीतिक तनाव को नई ऊंचाई दी है। भारत ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और चीन की किसी भी अस्वीकृति से यह तथ्य बदलने वाला नहीं है। देखा जाये तो आर्थिक असहजता और कूटनीतिक टकराव की यह दोहरी परिस्थिति भारत-चीन संबंधों की वास्तविक जटिलताओं को सामने लाती है।

वैसे तो भारत-चीन संबंध पिछले एक दशक में लगातार तनाव और सहयोग के बीच झूलते रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों की घटनाओं ने एक बार फिर यह रेखांकित कर दिया है कि बीजिंग के साथ किसी भी प्रकार की साझेदारी केवल आर्थिक पैरामीटर पर नहीं चल सकती। इसमें राजनीति, सुरक्षा, भू-राजनीति, और सबसे बढ़कर, संप्रभुता की व्याख्या का मुद्दा निर्णायक रूप से शामिल है।

सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की चिंताओं पर नजर डालें तो भारतीय कंपनियों को चीन से उन्नत तकनीक, कंपोनेंट्स और निवेश की आवश्यकता है, जिसे पूरा करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। लेकिन इन साझेदारियों में अचानक लगा ब्रेक यह संकेत देता है कि चीन भारत के साथ तकनीकी और पूंजी साझेदारी में पहले से कहीं अधिक सतर्क हो गया है।

PG Electroplast की तकनीकी साझेदारी महीनों से अटकी पड़ी है; ॥द्वह्यद्गठ्ठह्यद्ग ने अपनी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 26% हिस्सेदारी लेने की योजना रोक दी है और Bharti Group mæÚUæ Haier India के 49% अधिग्रहण का मामला भी चीनी अनुमोदन के इंतजार में ठहरा हुआ है। ये घटनाएं आकस्मिक नहीं हैं। चीन स्पष्ट रूप से किसी भी ऐसी गतिविधि को अनुमति देने से पहले दो बातों पर गंभीरता से विचार कर रहा है– पहला, उसकी तकनीक और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा; और दूसरा, भारत-चीन संबंधों की वर्तमान राजनीतिक संवेदनशीलता।

यहां यह याद रखना होगा कि भारत ने 2020 में सीमा तनाव के बाद Press Note 3 लागू किया था, जिसके तहत पड़ोसी देशों के किसी भी निवेश पर सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी गई। चीन इसे एक राजनीतिक संदेश की तरह देखता है। अब वह भी वैसी ही कड़ी जांच-पड़ताल भारत से जुड़ी हर तकनीकी व पूंजीगत परियोजना के लिए लागू कर रहा है। परिणाम यह है कि भारतीय उद्योग दो तरफ से फंस गया है– भारत की सराहनीय 'वैल्यू एडिशन' और 'लोकलाइजेशन' की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए चीन की तकनीक और मशीनरी जरूरी है, लेकिन चीन की मंजूरी और व्यवहार अनिश्चित होता जा रहा है।

दूसरी ओर, आर्थिक मोर्चे की उलझनें कूटनीति में उभरते तनाव से गहराई से जुड़ी हैं। शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक को 18 घंटे तक रोके जाने की घटना सिर्फ एक यात्री के साथ हुआ अनुचित व्यवहार नहीं थी; यह चीन के उस राजनीतिक दावे का परिचायक है जिसमें वह अरुणाचल को 'दक्षिण तिब्बत' कहकर भारत के हिस्से के रूप में मानने से इंकार करता है। यह दावा केवल मानचित्र पर नहीं, बल्कि अब यात्रियों के अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय नियमों तक में दखल देने लगा है।

भारत की कड़ी प्रतिक्रिया इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि यदि कोई देश किसी भारतीय नागरिक की वैध पहचान को ही चुनौती देने लगे, तो यह महज़ कूटनीतिक असहमति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और संप्रभुता पर प्रश्नचिह्न है। विदेश मंत्रालय का यह कहना कि चीनी अधिकारियों की कार्रवाई 'अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा संबंधी कई संधियों तथा स्वयं चीन के अपने नियमों का उल्लंघन' है, केवल तथ्यात्मक आरोप नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि भारत अब ऐसी हरकतों को महज 'घटनाएं' मानकर छोड़ने वाला नहीं।

उधर, चीन का आधिकारिक बयान, जिसमें उसने यात्री के साथ किसी भी 'हिरासत' या 'उत्पीड़न' से इंकार किया और साथ ही अरुणाचल को 'अवैध रूप से स्थापित भारतीय राज्य' बताया, वही पुराना दोहरा स्वर है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के पासपोर्ट-संबंधित निर्देश उसकी लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से भारतीय नागरिकों को असुविधा में डालने के साथ-साथ अपने दावे को बार-बार व्यवहारिक स्तर पर लागू करने का तरीका है।

देखा जाये तो ताज़ा घटनाएं यह बताती हैं कि भारत-चीन संबंधों में सुधार केवल बैठकों या बयानबाजी से नहीं होगा; इसके लिए एक लंबी, सावधानीपूर्वक और बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। जैसे- भारत को हर ऐसे मामले में न केवल द्विपक्षीय रूप से बल्कि ICAO, IATA और अन्य वैश्विक मंचों पर औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इससे चीन की सीमा-व्यवहार नीतियों की वैश्विक जांच बढ़ेगी। साथ ही चीन द्वारा तकनीकी सहयोग रोकने से भारत को अपनी 'टेक इकोसिस्टम' को और तेज़ी से विकसित करने का अवसर मिलता है। PLI स्कीम्स और R×D में निवेश को अब रणनीतिक प्राथमिकता बनाना होगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि कूटनीति केवल विरोध का नाम नहीं है। वार्ता जारी रखनी ही होगी, लेकिन स्पष्ट लाल रेखाओं के साथ। यह संदेश बीजिंग को समय-समय पर और तीखेपन से मिलता रहना चाहिए कि संप्रभुता और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भारत किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा।

बहरहाल, भारत-चीन संबंधों की आज की तस्वीर में सबसे बड़ी कमी 'विश्वसनीयता' की है और यह कमी दोनों दिशाओं से उत्पन्न होती है। जब बीजिंग तकनीकी सहयोग रोकता है, निवेश में देरी करता है और भारतीय नागरिकों की पहचान पर ही प्रश्न खड़ा करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संबंधों में अनिश्चितता बढ़ रही है। भारत के लिए यह समय भावनाओं का नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण दृढ़ता का है। आर्थिक साझेदारी जरूरी है, लेकिन सम्मान और संप्रभुता सर्वोपरि हैं। भारत ने शंघाई एयरपोर्ट घटना पर जो तीखी प्रतिक्रिया दी है, वह भविष्य के लिए आवश्यक संकेत है कि चाहे तकनीक की जरूरत हो या व्यापार की, भारत अपने नागरिकों और अपने क्षेत्रीय दावे पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा।

दक्षिण अफ्रीका से हार का भारी झटकाः WTC तालिका में भारत फिसला, पाकिस्तान से भी पिछड़ा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोलकाता। बुधवार को घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से शर्मनाक श्रृंखला हारने के बाद भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है। 2000 के बाद यह दूसरी बार है जब उन्होंने देश में टेस्ट श्रृंखला जीती है। इस बीच, आईसीसी के अनुसार, 408 रनों से हार भारत की टेस्ट क्रिकेट में रनों के अंतर से सबसे बड़ी हार है। इस जीत ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। गत चैंपियन अपने चार टेस्ट मैचों में 36 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर है। उनका अंक प्रतिशत (पीसीटी) 66.67 से बढ़कर 75 हो गया है। उन्होंने तीन टेस्ट जीते हैं और सिर्फ एक हारा है।

दूसरी ओर, भारत अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज पाकिस्तान से नीचे खिसक गया है, और अब वह पांचवें स्थान पर है, जिसका पीसीटी 48.15 पर आ गया है, जिसमें चार हारे, चार जीते और एक ड्रॉ रहा है। पहले दिन 247/6 के स्कोर के साथ धीमी शुरुआत के बाद, ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी (109) के पहले टेस्ट शतक और मार्को जेनसन (91 गेंदों में 93 रन, छह चौकों और सात छक्कों की मदद से) की जोरदार पारी ने निचले क्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रोटियाज को पहली पारी में 489 तक पहुंचाया। कुलदीप यादव (4/115) भारत के शीर्ष गेंदबाज रहे।

जेनसन ने गेंद से अपना जादू जारी रखा और 6/48 के आंकड़े हासिल किए, जिससे मेजबान टीम केवल 201 रन पर ढेर हो गई। यशस्वी जायसवाल (97 गेंदों में 58 रन, छह चौकों और एक छक्के की मदद से) और वाशिंगटन सुंदर (92 गेंदों में 48 रन, दो चौकों और एक छक्के की मदद से) के अर्धशतकों ने उल्लेखनीय प्रतिरोध पेश किया। भारत ने 65 रनों की साझेदारी के साथ अच्छी शुरुआत की, लेकिन सुंदर और कुलदीप (134 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 19 रन) के बीच 72 रनों की साझेदारी के साथ 122/7 पर फिसल गया, जिससे भारत 200 रनों के आंकड़े तक पहुंच गया।

दक्षिण अफ्रीका ने फॉलो-ऑन न देने का फैसला किया, बल्कि अपनी बढ़त को 500 के पार पहुँचाया। ट्रिस्टन स्टब्स (180 गेंदों में 94 रन, नौ चौकों और एक छक्के की मदद से) ने पारी घोषित होने से पहले अपनी तीसरी पारी में 260/5 का स्कोर बनाया। एक बार फिर स्पिनरों ने कमाल दिखाया, जिसमें जडेजा ने चौका लगाया। लेकिन भारत के सामने 549 रनों का विशाल लक्ष्य था। कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर ऑफ द मैच साइमन हार्मर दूसरी पारी में भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर थे। पहली पारी में 64 रन देकर 3 विकेट लेने के बाद, हार्मर (37 रन देकर 6 विकेट) ने आखिरी दिन की सुबह भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया।

यादव महासभा ने शहीद को दी श्रृद्धांजलि

हमीरपुर- जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मरे सेना के नायक गोविंद सिंह को यादव महासभा ने उसके पैतृक घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करके जवान के परिजनों को ढांढस बंधाया। महासभा के जिला मीडिया प्रभारी नंदकिशोर यादव ने बताया कि सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के कुसमरा गांव निवासी गोविंद सिंह सेना में नायक पद पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात था। गलत 23 नवंबर को ड्यूटी के दौरान गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। 25 नवंबर को सेना के वाहन से देर शाम शव को गांव लाया गया सूर्यास्त हो जाने के कारण मंगलवार को जवान का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। बुधवार को जवान का गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष सुघर सिंह यादव, राजकिशोर यादव, महासचिव रमाशंकर यादव, बदलू फौजी, अनार सिंह आदि शामिल रहे और जवान को श्रद्धांजलि देकर परिजनों को ढांढस बधाते हुए सांत्वना प्रदान की।

प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान में निहित आदर्शों और कर्तव्यों का पालन करे- महेन्द्र कुमार पांडेय

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- संविधान दिवस के अवसर पर जनपद न्यायालय, हमीरपुर के सभागार में गरिमामय वातावरण में प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर द्वारा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर मनोज कुमार राय के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर न्यायालय परिवार के सभी न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के संविधान की भावना को नमन करते हुए किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेन्द्र कुमार पाण्डेय ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने संविधान दिवस के महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान में निहित आदर्शों और कर्तव्यों का पालन करे तथा देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाए। इस अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया गया। तथा संविधान के प्रति निष्ठा रखे जाने की शपथ दिलाई गई। उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना को उत्साहपूर्वक वाचन किया गया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा एवं सम्मान प्रकट किया। कार्यक्रम के अंत में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर ने सभी का आभार व्यक्त किया और संविधान की भावना को जन-जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

वन स्टॉप सेंटर में बच्चों-बच्चियों को गुड़ टच और बेड टच के बारे में किया जागरूक

हमीरपुर- कुरारा ब्लॉक के गिमुहा ग्रामपंचायत स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में वन स्टॉप सेंटर वा हब फॉर इम्पावरमेंट के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बालक बालिकाओं को बाल अधिकार एवं बाल विवाह गुड टच बैड

टच की जानकारी दी गई, वन स्टॉप सेंटर से तबस्सुम परवीन (केस वर्कर) द्वारा समस्त टॉल फ्री नंबरों 112, 1098, 1090,181,1076,की जानकारी दी गई, वही दूसरी ओर HEW से आकिफ़ अहमद (जे एस) द्वारा महिला कल्याण विभाग की ओर से चलने वाली समस्त योजनाओं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, स्पॉन्सरशिप, निराश्रित महिला पेंशन की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।

पंजाब के बटाला में हत्या का संदिग्ध गिरफ्तार

पंजाब के बटाला में मुठभेड़ के बाद हत्या के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि माणिक, दीप चीमा की हत्या के मामले में वांछित था, जिसकी दो नवंबर को गुरदासपुर जिले के बटाला में खोखर पैलेस के पास पांच हमलावरों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। चीमा हत्याकांड में पुलिस पहले ही दो हमलावरों - हरविंदर और सविंदर - को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस उप महानिरीक्षक (बॉर्डर रेंज) संदीप गोयल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि माणिक रविवार को मोटरसाइकिल पर खुलियान गांव की तरफ से आ रहा है। गोयल ने बताया कि जब माणिक को रुकने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं, जवाबी कार्रवाई में माणिक को गोली लगने से वह घायल हो गया। उन्होंने बताया कि माणिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोयल ने कहा कि चीमा हत्याकांड के बाकी दो आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

संविधान दिवस (26 नवंबर) के अवसर पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में भीम आर्मी/ आज़ाद समाज पार्टी (काशीराम) के अगुवाई में कार्यक्रम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल- शहडोल में भीम आर्मी/आज़ाद समाज पार्टी का कार्यक्रम, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और संगठन के सूत्रों के अनुसार, शहडोल में संविधान दिवस, को 'राष्ट्रीय कानून दिवस' के रूप में मनाने मनाया गया है। शहडोल शहर के प्रमुख स्थान (डॉ. अंबेडकर पार्क/प्रतिमा स्थल) पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी एकत्रित हुए! **रैली-** संविधान के संदेश को आम जनता तक पहुँचाने के लिए शहर के मुख्य मार्ग पर जागरूकता जुलूस, वाहन रैली निकाली गई! जिसमें 'जय भीम' भीम आर्मी जिंदाबाद, और 'संविधान बचाओ' संविधान दिवस अमर रहे , के नारे लगाए गये। **यह कार्यक्रम,** संविधान की सर्वोच्चता और डॉ. अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त करने पर केंद्रित रखा गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं में संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रस्तावना के सामूहिक वाचन से हुआ! जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अध्यापक, समाजसेवी तथा स्थानीय नागरिक शामिल हुए। वक्ताओं ने संविधान निर्माताओं के योगदान, डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम में आयोजित विचार-गोष्ठी, संगोष्ठी, प्रतिभागियों ने संविधान के विभिन्न पक्षों–न्याय,स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मौलिक अधिकारों–पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सामाजिक संगठनों ने भी इस अवसर पर जागरूकता रैली निकाली, जिसमें नागरिकों को कानून का सम्मान करने, भेदभाव का विरोध करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में, एड.श्यामलाल जैसवाल, भीम आर्मी जिला संयोजक राजेश कुशवाहा, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष शहडोल कैलाश अहिरवार, शिव बैगा, गोलू बौद्ध, श्री मति लक्ष्मी साहू, रामसजीवन कोल, प्रकाश वर्मा, रामस्वरूप कोल, सूरज बैगा, डॉक्टर राजेश अहिरवार, एडवोकेट चांदनी अहिरवार, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन जिला अध्यक्ष शहडोल चंद्रशेखर साकेत एवं सभी मैकी ग्रामवासी के नेतृत्व में कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान रहा है!

वोट चोर का झूठा नारा देने वाली कांग्रेस खुद है रिजर्वेशन चोरः पेरिका सुरेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। बीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नवनियुक्त कन्वीनर पेरिका सुरेश ने बशीरबाग प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर वोट चोरी का लगातार आरोप लगा रहे हैं,जबकि सच्चाई यह है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार तेलंगाना पंचायत चुनाव में बीसी समाज के आरक्षण की चोरी कर रही है।तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पंचायत चुनाव में बीसी के निर्धारित आरक्षण 42% को घटाकर 18% कर दिया है।उन्होंने कहा कि इस समाज को 5300 सीटों पर आरक्षण का अधिकार है, जिसे घटाकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने 2500 कर दिया है।यह बीसी समाज के साथ घोर अन्याय है। तेलंगाना के 30 मंडलों को आरक्षण से वंचित कर दिया गया है,वही 80 मंडलों में एक या दो सीट रिजर्व किया गया है।श्री सुरेश ने कहा कि बीसी समाज सरकार के इस समाज विरोधी फैसले का राज्यव्यापी विरोध करेगी।आगामी 8,9 दिसंबर को बीसी समाज अपने 42 परसेंट आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली में संसद भवन का घेराव कर 42% आरक्षण के लिए मांग पत्र सौंपेगी। इस अवसर पर बीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के1000 सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरपर्सन जाजुला श्रीनिवास गॉड,वर्किंग चेयरमैन गुंजा कृष्ण,कुंदरम गणेश चारी,बीसी वेलफेयर एसोसिएशन स्टेट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कुलकाचारला श्रीनिवास मुदीराज,स्टूडेंट एसोसिएशन सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट तातीकोंडा विक्रम गॉड,यूथ एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट कानाकला श्याम उपस्थित रहे।

श्री गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन निकली भव्य कलश यात्रा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुरः सुमेरपुर में श्रीगायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा की शुरुआत श्री गायत्री विद्या मंदिर इंटर कालेज से हुई। जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महिलाएं सिर में कलश रख कर शोभायात्रा में आगे बढ़ी। सिर पर कलश धारण किए महिलाओं, युवा वर्ग और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें माहौल भक्तिमय हो गया। रास्ते भर जगह-जगह यात्रा का पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया गया। वहीं बैंड-बाजे और आकर्षक झांकियों ने यात्रा की भव्यता को और बढ़ा दिया।

कथा स्थल पर पहुंचने के बाद कथा व्यास पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने विधि-विधान से कलश स्थापना कर पूजन संपन्न कराया। उन्होंने पुराणों में वर्णित कलश स्थापना के महत्व को विस्तार से बताते हुए कहा कि कलश दिव्य ऊर्जा, शांति और

समृद्धि का प्रतीक है। जल, पंचतत्वों और देव शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कलश की स्थापना से वातावरण शुद्ध होता है तथा घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सनातन परंपरा में कलश केवल एक पात्र नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना गया है। इस मौके पर कथा परीक्षित कैलाश सोनी,रानी देवी,नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेंद्र शिवहरे,राजकुमार सोनी सहित बड़ी संख्या लोग मौजूद रहे। उधर यज्ञवेदी में तीसरे दिन भी गायत्री महामंत्र का जाप जारी रहा। 24 लाख मंत्र जाप के उपरांत के पूर्णाहुति के यज्ञ का समापन होगा। यज्ञवेदी में आचार्य माधवानारायण शास्त्री एवं यज्ञ के ब्रह्मा पंडित बलदेव प्रसाद शास्त्री, सह आचार्य उमादत शुक्ला के निर्देशन में कर्मकांडी ब्राह्मण मंत्र जाप में लगे हुए हैं। साथ ही मेला मैदान में महिलाएं घर गृहस्थी सामान खरीदने के साथ झूला आदि का आनंद ले रहे हैं। महायज्ञ के आयोजकों ने बताया कि पूरे सप्ताह चलने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन भजन, कथा और यज्ञ की विशेष श्रृंखलाएं आयोजित होंगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है।

तहसील स्तरीय दिब्यांग क्रीड़ा प्रतियोगिता में दिव्यांगों ने दिखाई प्रतिभा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- मौदहा कस्बा के ब्लॉक संसाधन केंद्र में तहसील स्तरीय दिब्यांग क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमे मौदहा और मुस्करा ब्लॉक के प्रतिभागियों ने भाग लिया कार्यक्रम का आरंभ खण्ड शिक्षा अधिकारी ने सरस्वती मां के चित्र पर माल्यार्पण कर किया।

कस्बे के बीआरसी में समग्र शिक्षा के तहत तहसील स्तरीय दिब्यांग क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमे तहसील के दोनों विकास खण्डो मौदहा और मुस्कुरा के दिब्यांग बच्चों ने भाग लिया कार्यक्रम का आरंभ खण्ड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार कमल ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया इस दौरान दौड़, कुर्सी दौड़, रस्साकसी सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमे दौड़ प्रतियोगिता में इमरान, अनुभव प्रथम,पीयूष और दीपक दितीय,रवि और अर्चना तृतीय स्थान पर रहे।

वहीं कुर्सी दौड़ में सिलौली के अंश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।जबकि बालिका वर्ग दौड़ प्रतियोगिता में मुटनी की दिब्याशीं प्रथम और अरतरा की राधा दितीय स्थान पर रहीं।इस दौरान स्पेशल एजुकेटर मयंक कुमार, अजीत सचान,मनोज तिवारी, हरिराम सहित अन्य शिक्षक और अभिवावक मौजूद रहे। जबकि प्रतियोगिता में

प्रथम, दितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर उनका उत्साह वर्धन किया गया।